



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082020-221258
CG-DL-E-20082020-221258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2020/ श्रावण 29, 1942

No. 204]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2020/SHRAVANA 29, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

प्रारंभिक जाँच परिणाम

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

मामला सं. एडीडी(ओआई)-02/2020

विषय : थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहाँ से भारत में निर्यातित “फेनोल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच के प्रारंभिक जाँच परिणाम।

फा. सं. 6/3/2020-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मै. दीपक फेनोलिक्स लि., मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक्स कैमिकल्स लि. और मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लि. (जिन्हें यहाँ आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से “फेनोल” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद”, “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लागू करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 25 फरवरी, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जाँच की शुरुआत की गई थी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनराश्री शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत की कार्यवाही से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 फरवरी, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने 25 फरवरी, 2020 की जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्तों के अनुसार भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर निर्धारित तरीके और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों के जरिए उनकी सरकार को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।
- ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पत्तों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध करने पर उत्तर तथा अनुरोध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों हेतु समयसीमा बढ़ाई थी। 4 अप्रैल, 2020 के पत्र द्वारा समय सीमा 24 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाई गई। 23 अप्रैल, 2020 के पत्र द्वारा समय सीमा 10 मई, 2020 तक बढ़ाई गई थी और 11 मई, 2020 के पत्र द्वारा समय सीमा 20 मई, 2020 तक बढ़ाई गई थी।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं :
- मै. पीटीटी फेनोल कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
 - मै. डेकोटा ग्लासिफिकेशन कंपनी, यूएसए,
 - मै. डॉ कैमिकल कं., यूएसए,
 - मै. गिओरिया गल्फ, यूएसए,
 - मै. शैल कैमिकल्स, यूएसए
 - मै. एडवानसिक्स, यूएसए
 - मै. इनिओस फेनोल, यूएसए
- ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।
- मै. पीटीटी फेनोल कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल), थाइलैंड,
 - मै. मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) पीटीई लिमिटेड (एमएपी), सिंगापुर,
 - मै. मित्सुई एंड कंपनी लि. (एमबीके), जापान

- iv. मै. केमपार एनर्जी पीटीई लि. (केमपार), सिंगापुर
- झ. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं।
- i. मै. सी. जे. शाह एंड कंपनी;
 - ii. मै. हरेश कुमार एंड कंपनी;
 - iii. मै. पीसीएल ऑयल एंड इंडस्ट्रीज;
 - iv. मै. कांतिलाल मनीलाल एंड कंपनी प्रा. लि.;
 - v. मै. सोनकमल इंटरप्राइजेज;
 - vi. मै. खेतान ब्रदर्स;
 - vii. मै. शुभम डाइज एंड कैमिकल्स लिमिटेड;
 - viii. मै. एक्रॉन इंटरप्राइजेज;
 - ix. मै. नाइकनावरे कैमिकल्स लिमिटेड;
 - x. मै. पारस डाइज एंड कैमिकल्स लिमिटेड;
 - xi. मै. टोरेट फार्मास्युटीकल लिमिटेड;
 - xii. मै. यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड;
 - xiii. मै. रेजिंग एंड प्लास्टिक लिमिटेड;
 - xiv. मै. कैलाश पॉलीमर्स;
 - xv. मै. सेंट्रम मेटालीज प्रा. लिमिटेड;
 - xvi. मै. वंडर लेमिनेट्स प्रा. लिमिटेड;
 - xvii. मै. मेघदेव इंटरप्राइजेज;
 - xviii. मै. सतगुरु इंटरनेशनल;
 - xix. मै. हाई पॉलीम लैब्स लिमिटेड;
 - xx. मै. रेनबो कलर्स एंड कैमिकल्स;
 - xxi. मै. ब्लीच मार्केटिंग प्रा. लि.;
 - xxii. मै. कारमैन इंटरनेशनल (पी) लि.;
 - xxiii. मै. कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा.लि.;
 - xxiv. मै. एनजीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड;
 - xxv. मै. फार्मसन फार्मास्युटीकल गुजरात लिमिटेड;
 - xxvi. मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लि.;
 - xxvii. मै. सिंह प्लास्टिसाइजर्स एंड रेजिन्स (आई) प्रा.;
 - xxviii. मै. नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि.;
 - xxix. मै. कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड;
- ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।
- i. मै. आइका लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेटलिमिटेड;
 - ii. मै. ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज लिमिटेड;
 - iii. मै. क्लीन साइंस एंड टेक प्रा. लिमिटेड;

- iv. मै. मेघमनी आर्गेनिक्स लिमिटेड;
 - v. मै. अकिन कैमिकल्स प्रा.लिमिटेड;
 - vi. मै. अतुल लिमिटेड;
 - vii. मै. विग्रो लेमिनेट्स लिमिटेड;
- ट. निम्नलिखित पक्षकारों ने ज्ञात शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में विधिक अनुरोध दायर किए हैं।
- i. मै. क्लीन साइंस एंड टेक प्रा. लिमिटेड;
 - ii. मेघमनी आर्गेनिक्स लिमिटेड;
 - iii. अकिन कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड;
 - iv. हरेश पैट्रोकेम प्रा. लिमिटेड;
 - v. गीतांजलि कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड;
 - vi. अतुल लिमिटेड;
 - vii. सेंट प्लाई;
- ठ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी।
- i. इंडियन लेमिनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - ii. दि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमैन
- तथापि, किसी भी प्रयोक्ता एसोसिएशन ने जाँच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है।
- ड. प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।
- ढ. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाच अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (6 महीने) की है। क्षति जाँच अवधि पर 1 अप्रैल, 2016-31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017-31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018-30 जून, 2019 और जाँच अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- ण. प्राधिकारी ने पीओआई सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु हेतु 14 बार आयात आंकड़ों को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और डायरक्रेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट (डीजीएस) से प्राप्त किया और सौदों की आवश्यक जाँच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।
- त. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उसे बेचने के लिए तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की पटल अध्ययन के माध्यम से आवश्यक सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई थी। आवश्यक सुधार, जहाँ लागू हो, सहित केवल ऐसी सूचना पर प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- द. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- ध. जहाँ कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जाँचमें काफी बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जाँच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- न. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में साक्ष्यों के समर्थित तथा संगत मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी आगे प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँचकरेंगे जो अंतिम जाँच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।
- प. इस प्रारंभिक जाँच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।
- फ. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जाँच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.67 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जाँच शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

“वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद फेनोल है। इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात् बल्क और पैकड में बेचा जाता है। बल्क पैकड बिक्रियां आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि बिक्रियां काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकती हैं और उन्हें सामान्यतः ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मेलडीहाइड रेजिन्स, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है।”

इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- क. फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात् बल्क और पैकड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियाँ आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि पैकड पारेषण काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकती हैं और उन्हें सामान्यतः ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मेलडीहाइड रेजिन्स, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है।

- ख. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

- ग. आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं क्योंकि ये रासायनिक और तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई और संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों ने आयातित उत्पाद की समान उत्पाद का उत्पादन किया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. *‘वर्तमान जाँचमें विचाराधीन उत्पाद फेनोल है।*

8. फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों अर्थात् बल्क (खुले में) और पैकड में बेचा जाता

है। बल्क बिक्रियाँ आम तौर पर खुले रूप में होती हैं जबकि पैकड पारेषण काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकते हैं और उन्हें सामान्यतः ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनाल फार्मेलडीहाइड रेजिन्स, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टीकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल्स, भेषजों, डाईफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है।

9. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँचके दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
10. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। आवेदक की दलील को किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवादित नहीं ठहराया है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
- क. आवेदकों अर्थात् दीपक फेनोलिक लिमिटेड, हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और एस आई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के पास भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।
- ख. आवेदकों ने संबद्ध देशों से पीओआई में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
- ग. आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं :-
13. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-
“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘घरेलू उद्योग’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।
14. यह आवेदन दीपक फेनोलिक लिमिटेड, हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और एस आई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है क्योंकि आवेदकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदकों ने दावा किया है कि न तो उन्होंने पी ओ आई में संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के आयातक से संबंधित हैं।
15. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और यह भी मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के पीपीसीएल और एमबीके द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में गोपनीय होने का दावा किया गया है। इसके अलावा, निर्यातकों में प्राधिकारी की व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के प्रावधानों से अधिक अत्यधिक

गोपनीयता का दावा किया है। एमबीके ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का भाग-iv प्रस्तुत नहीं किया है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के प्रावधानों में विहित दिशानिर्देशों को पूरा नहीं किया है।
18. यदि आवेदकों ने आवेदन के गोपनीय अंश में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने संबंधी तर्क दिया है तो यह स्पष्ट रूप से गोपनीयता के प्रावधानों का उल्लंघन है। चूंकि उन्हें अगोपनीय अंश में नहीं दिया गया है। अगोपनीय अंश में तर्क प्रदान करने में आवेदकों की असमर्थता उन पर सार्थक टिप्पणी करने की हितबद्ध पक्षकारों की सक्षमता को बाधित करती है और उन्हें इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने हितों के संरक्षण में असमर्थ बनाती है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

20. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है (उदाहरणार्थ क्योंकि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर जिससे सूचना प्राप्त की गई है, अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा) या इसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, उसका उचित कारण देने पर प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना का उसे देने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।
21. प्राधिकारी ने आवेदकों और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा है।
22. जहाँ तक शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के तर्कों का आवेदन के अगोपनीय अंश में नहीं होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुत पत्रों के जरिए शुल्क को पूर्वव्यापी रूप में लागू करने का अनुरोध किया है। पत्रों के अगोपनीय अंश को आवेदकों द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. विभिन्न मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए कानून के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों का वर्तमान मामले में पूरी तरह पालन हुआ है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है: (क) पूर्वव्यापी आधार पर एडीडी लागू करना, और (ख) जांच के परिणाम के आने तक आयात का आकलन अनंतिम रूप से करना
- ख. पीओआई के भीतर अत्यधिक तीव्र क्षति होने के कारण, जो पीओआई के बाद और अधिक बढ़ गई है, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अत्यधिक क्षति के निवारण हेतु शुल्क के बैच मार्क रूप को लागू करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

24. विभिन्न मुद्दों के बारे में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
- क. आवेदकों ने आवेदन में पूर्वव्यापी एडीडी लागू करने के अनुरोध के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। सार्वजनिक फाइल में भी इस तर्क संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है।
- ख. एडीडी को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। कराधान कानून का मूल सिद्धांत करदाता के लिए निश्चितता और पूर्वानुमेयता होता है और इसलिए कर और शुल्क भावी प्रकृति के होते हैं। पूर्वव्यापी रूप से लागू करना एडीडी के मानकों के भी विरुद्ध है। इससे उचित आयातक और प्रयोक्ता के विरुद्ध पक्षपात होता है। अधिनियम की धारा 9क(3) में केवल दुर्लभ और असाधारण स्थितियों की दशाओं सहित अपवादों की व्याख्या है, (क) पाटन का इतिहास और (ख) अल्प अवधि में भारी पाटन। आवेदकों द्वारा अपने दावे का सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है। पाटन का इतिहास उस देश के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिसके विरुद्ध जांच चल रही है। अनेक जाँचों में घरेलू उद्योग द्वारा पूर्वव्यापी शुल्क का अनुरोध किया गया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई शुल्क लगाया नहीं गया था जो स्पष्टतः दर्शाता है कि यह ऐसा प्रावधान है जिसमें असाधारण परिस्थितियों का मौजूद होना और उनका प्रयोग किया जाना अधिदेशित है। डी आई ने असाधारण परिस्थितियाँ सिद्ध नहीं की हैं। प्राधिकारी को शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने की सिफारिश करने से पहले अपेक्षित दशाओं का पूरा होना सुनिश्चित करना होगा। स्थितियाँ मौजूद हैं यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदकों का है और अगोपनीय याचिका में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है।
- ग. प्राधिकारी ने इतनी कम पीओआई अपनाने का कोई कारण नहीं बताया है और इसलिए जाँच शुरुआत संबंधी सूचना नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है। प्राधिकारी ने पूर्व में अनेक जाँचों में कम पीओआई को निरंतर अस्वीकार किया है और आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पीओआई से अधिक पीओआई पर जांच की शुरुआत की है।
- घ. मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड अवश्य शुरुआती दिक्कतों और तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा होगा। संयंत्र भी आंतरिक कारणों की वजह से बंद हुआ था।
- ड. फेनोल के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति या वास्तविक क्षति के खतरे का आकलन करने के लिए एक और पाटनरोधी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राधिकारी ने विगत 17 वर्षों में फेनोल संबंधी अनेक पाटनरोधी जांच की हैं। 2019 में मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने फेनोल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी से संपर्क किया था जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था। मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने आयातों की प्रतिबंधित सूची में फेनोल उत्पाद को शामिल करने के लिए आवेदन किया था तथापि, रसायन मंत्रालय ने उस अस्वीकृत कर दिया था।
- च. प्रयोक्ता उद्योग आयातों पर निर्भर हैं क्योंकि भारत में फेनोल के लिए मांग-आपूर्ति अंतर है।
- छ. आवेदक मासिक विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी को कोई अनिवार्य कारण बताने में विफल रहे हैं। डीजीटीआर नियम पुस्तिका में उन परिदृश्यों का उल्लेख है जिनमें ऐसा विश्लेषण किया जा सकता हो जिनमें कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन लागत में व्यापक अंतर होना शामिल है। जैसा स्वीकार किया गया है, कच्ची सामग्री की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। मासिक पाटन आकलन के लिए मासिक लागत आंकड़ों को मंगाना होगा, जो एक भारी भरकम प्रक्रिया है। प्राधिकारी एक सरकारी अधिसूचना जारी करें और इसलिए ऐसी सूचना के लिए समय प्रदान करें। यह प्रक्रिया अनंतिम जाँच परिणाम से पहले पूरी करनी होगी।

च.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के मतों पर निम्नानुसार विचार किया है :

- क. एडीडी को पूर्वव्यापी रूप से लगाने पर अंतिम निर्धारण में विचार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी इस मुद्दे का निर्णय करते समय सभी हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों पर विचार करेंगे।
- ख. पीओआई के रूप में छह महीने के चयन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि छह महीने को पीओआई के रूप में अपनाया जाना नियमावली से असंगत नहीं है बशर्ते कि आवेदक ऐसी समयावधि की आवश्यकता को सत्य सिद्ध करें और प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकृत किया जाए। इस मामले में आवेदकों ने कारण बताते हुए छह महीने की जांच अवधि पर विचार करने की जरूरत को साक्ष्यांकित किया है कि इस अवधि में पाटन शुरू हुआ है और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि इस तथ्य के मद्देनजर छह महीने की पीओआई की चीन जन.गण. ने मई, 2019 में संबद्ध देशों पर एडीडी लगाया था जिसके कारण भारत को संबद्ध देशों से आयात कीमतों में भारी गिरावट आई थी। इस उत्पाद का निर्यात अप्रैल और मई, 2019 महीने में काफी अधिक कीमत पर हुआ था। इस प्रकार अप्रैल और मई, 2019 को शामिल करने का अर्थ “पाटन नहीं हाने की अवधि” को शामिल करना होता। ऐसी अवधि को निर्धारित करना उचित नहीं होगा जिसमें पाटन का कोई आरोप न हो।
- ग. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तर्क प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन हुआ है और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में अधिसूचना सं. 9/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई है जिसमें नियम 2(घ क) और नियम 22 के स्पष्टीकरण को निम्नलिखित उपबंधों सहित शामिल किया गया है :

“जांच की अवधि –

- (i) जांच की शुरुआत की तारीख के अनुसार 6 महीने से अधिक पहले की नहीं होगी”
- (ii) 12 महीने की अवधि होगी और ऐसे कारण जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किए जाएंगे, से 6 महीने की न्यूनतम या 18 महीने की अधिकतम अवधि पर विचार किया जा सकता है “।

- घ. आवेदकों के तर्कों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने ऊपर यथाउल्लिखित आवेदकों द्वारा प्रदत्त औचित्य के अनुसार पीओआई के रूप में 6 महीने के चयन को उचित समझा है क्योंकि ऐसी अवधि निर्धारित करना उचित नहीं होगा जिसमें पाटन का कोई आरोप न हो।
- ड. मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड द्वारा शुरुआती लागत और तकनीकी समस्याओं का सामना करने संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने अपनी आरंभिक लागत का पूर्णतः पूंजीकरण किया है और उसे क्षति संबंधी आंकड़ों में शामिल किया गया है। इसके अलावा, कंपनी को 2018-19 में भी उत्तम क्षमता उपयोग प्राप्त हुआ है और इसलिए कंपनी की उत्पादन लागत नई उत्पादन सुविधाओं के संभावित अल्प उपयोग के कारण अधिक नहीं हो सकती है।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न मंचों से संपर्क करने और राहत की मांग करने संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि औद्योगिक उद्यम का यह विशेषाधिकार है कि वह विभिन्न सांविधिक या विनियामक उपबंधों के अंतर्गत राहत की मांग करे।
- छ. मांग-आपूर्ति में अंतर संबंधी तर्क के संदर्भ में प्राधिकारी मानते हैं कि संभावित मांग आपूर्ति अंतर क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों के विरुद्ध राहत की मांग से घरेलू उद्योग को वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है।
- ज. शुल्क के रूप से संबंधित घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुसार प्राधिकारी का अधिदेश कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करना और शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करना है जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, पाटनरोधी उपाय के रूप की उपयुक्तता का निर्णय मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए किया जाता है।

झ. क्षति विश्लेषण वार्षिकीकृत आंकड़ों की तुलना द्वारा क्षति अवधि के लिए किया गया है और न कि मासिक आधार पर किया गया है। क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और कीमत कटौती का निर्धारण पूरी जाँच अवधि तथा समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

26. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदकों ने थाइलैंड के लिए साउथ ईस्ट एशिया और यूएसए के लिए यू एस गल्फ में मासिक कीमतों हेतु आईसीआईएस बुलेटिन पर विचार किया है। कारखाना द्वार कीमत निर्धारित करने के लिए सीएफआर कीमतों में संगत समायोजन किए गए हैं।

ख. आवेदकों ने सीआईएफ कीमत को लिया है और उसे समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजित किया है।

ग. दोनों संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

घ. भारित औसत आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत इस कारण वश पाटन की मात्रा का समाधान नहीं करेगी कि सामान्य मूल्य में संगत अंतर के बिना समयावधि के भीतर निर्यात कीमत में भारी अंतर रहा है। इसके अलावा, चूंकि सामान्य मूल्य में कोई खास अंतर नहीं है और इस अवधि में केवल निर्यात कीमत में परिवर्तन हुआ है, इसलिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के भारित औसत आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन त्रुटिपूर्ण होगा। सामान्य मूल्य को भारित आधार पर निर्धारित करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा और उसकी तुलना अलग-अलग निर्यात सौदों की कीमतों से करना उचित है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. थाइलैंड से भारत को निर्यात केवल बल्क रूप में हैं परंतु, घरेलू बिक्री बल्क और पैकड दोनों रूप में है। प्राधिकारी से उचित तुलना हेतु आवश्यक समायोजन करने का अनुरोध किया है।

ख. आवेदक थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य ज्ञात करते समय किए गए समायोजनों का कोई वैध परिकलन या औचित्य बताने में विफल रहे हैं।

ग. आवेदकों ने आईसीआईएस रिपोर्ट से सामान्य मूल्य के लिए कारखाना द्वार कीमत निर्धारित करने हेतु कोई समायोजन विनिर्दिष्ट नहीं किया है। भरोसा की गई आईसीआईएस रिपोर्ट की वैधता अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आईसीआईएस रिपोर्ट संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में कीमतों का परिकलन करती है। यदि आईसीआईएस रिपोर्ट स्थानीय कीमत, घरेलू कीमतविनिर्दिष्ट करती है तो आवेदकों ने गणना हेतु समुद्री भाड़े को गलत ढंग से समायोजित किया है। यदि आईसीआईएस रिपोर्ट में स्थानीय कीमतें विनिर्दिष्ट नहीं हैं तो प्राधिकारी ऐसे आधार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।

घ. कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत की गणना हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा के संबंध में समायोजनों की मांग की गई है। तथापि, आवेदक किए गए समायोजनों के बारे में पर्याप्त सूचना और औचित्य बताने में विफल रहे हैं।

ड. मूल आवेदन में पैकड फेनोल की निर्यात कीमत को बल्क फेनोल की निर्यात कीमत से कम गलत ढंग से दर्शाया गया है जबकि अद्यतन याचिका में अलग कीमतों का उल्लेख नहीं है। गणनाओं और साक्ष्यों की सत्यता और विश्वसनीयता की इस कारणवश प्राधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए।

च. बल्क और पैकड फेनोल के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन परिकलित किए गए हैं। तथापि, कोई अलग सामान्य मूल्य परिकलित नहीं हुआ है। इसके अलावा, केवल मूल जाँच में अलग निर्यात कीमत परिकलित की गई है। यह अस्पष्ट है कि ऐसा अलग पाटन मार्जिन कैसे परिकलित हुआ। प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पाटन का अलग-अलग मार्जिन कृपया निर्धारित करें।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

28. अधिनियम की धारा 9क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।
29. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के विहित उत्तर प्रस्तुत करके इस जांच में सहयोग किया है :
- पीटीडी फेनोल कंपनी लिमिटेड (पीपीसीएल), थाइलैंड;
 - मै. मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई. लि. (एमएपी), सिंगापुर;
 - मै. मित्सुई एंड कं. लि. (एमबीके) जापान;
 - मै. केमपार एनर्जी पीटीई. लि. (केमपार) सिंगापुर;
30. यह नोट किया जाता है कि पीपीसीएल थाइलैंड में आधारित एक उत्पादक और निर्यातक है। पीओआई के दौरान पीपीसीएल ने भारत में अपने उपभोक्ताओं और इन सभी तीन पक्षों को अपने उत्पाद बेचे हैं जो व्यापारी कंपनियां हैं और जिन्होंने भारत में ग्राहकों को उत्पाद बेचा है। एमएपी, एमबीके और कैमपार थाइलैंड बाजार में पीयूसी की घरेलू बिक्री में शामिल नहीं थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीपीसीएल और घरेलू उद्योग ने फेनोल के बल्क और पैकड रूपों में अंतर के कारण आवश्यक समायोजनों का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक आधार पर उनके अनुरोधों पर विचार किया है और यह नोट किया है कि शामिल पक्षों से अतिरिक्त आंकड़े और साक्ष्यों के संग्रहण के बाद इस मुद्दे का और विस्तृत आकलन आवश्यक है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए फेनोल के बल्क/खुले रूप के सामान्य मूल्य के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीपीसीएल के उत्तर के अनुसार परिशिष्ट 4क में घरेलू बिक्री सौदों में उल्लिखित विवरणों में फेनोल के विभिन्न रूपों अर्थात् बल्क या पैकड को नहीं दर्शाया गया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ जांच की प्रक्रिया के दौरान आगे जांच होने तक पीपीसीएल की सभी घरेलू बिक्रियों पर बल्क/खुले रूप में विचार किया है।
31. यूएसए से किसी उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण**थाइलैंड****पीपीसीएल, थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य**

32. थाइलैंड से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक अर्थात् पीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान घरेलू बिक्रियां असंबद्ध ग्राहकों को की गई हैं। प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी ने अनिवार्य परीक्षण हेतु उचित लागत आंकड़ों सहित संबंधित परिशिष्टों में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बिक्री कीमत संबंधी व्यौरे प्रदान किए हैं। सामान्य मूल्य के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि *** अम.डा./एमटी की कीमत पर घरेलू बाजार में *** एमटी की बिक्री की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में निर्यातों की मात्रा की तुलना में घरेलू बिक्रियों की मात्रा पर्याप्त है। इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदों के लाभप्रद होने के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया

परीक्षण किया है। यदि लाभ वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार करते हैं जहां लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम होते हैं, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जाता है। व्यापार के सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां मात्रा के अनुसार 80 प्रतिशत से कम थीं। इसके अलावा पीपीसीएल ने कारखाना द्वार व्यय के रूप में अंतरदेशीय भाड़े, भंडारण लागत, ऋण लागत, सर्वेक्षण लागत और अन्य संबंधित समायोजनों का दावा किया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के अधीन पीपीसीएल के दावों को स्वीकृत किया गया है। पीपीसीएल द्वारा दावा किए गए समायोजनों को अनंतिम रूप से सत्यापित और विस्तृत सत्यापन के अधीन स्वीकृत किया गया है। डी जी सी आई एंड एस और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से प्राप्त आयात सूचना के पठन से यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के सभी आयात बल्क/खुले रूप में ही हुए थे और इसलिए पैकड/ड्रम फेनोल हेतु अलग सामान्य मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। इस प्रकार अनंतिम रूप से निर्धारित पीपीसीएल का सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

थाइलैंड में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात सूचना के पठन से यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के सभी आयात बल्क/खुले रूप में ही हुए थे और इसलिए पैकड/ ड्रम फेनोल हेतु अलग सामान्य मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। थाइलैंड में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनंतिम रूप से सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं और उसे निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यूएसए में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएसए से किसी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। यह नोट किया जाए कि आवेदक ने आईसीआईएस रिपोर्ट के आधार पर यूएसए में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यूएसए में सामान्य मूल्य संबंधी कोई सूचना नहीं दी है और यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि यह सबूत उचित नहीं है। डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात सूचना के पठन से यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के सभी आयात बल्क/खुले रूप में ही हुए थे और इसलिए पैकड/ ड्रम फेनोल हेतु अलग सामान्य मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। अतः यू एस के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों अर्थात् आईसीआईएस रिपोर्ट में दी गई कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

पीपीसीएल थाइलैंड के लिए निर्यात कीमत

35. पीपीसीएल ने अपनी असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों अर्थात् मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड (“एमबीके”), मित्सुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई लि. (“एमएपी”), कैमपार एनजी पीटीई लि. (“कैमपार”), ट्रेडकैम इंटरनेशनल एफजैडई (“ट्रेडकैम”) और रीवरएज इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड (“रीवरएज”) के साथ प्रश्नावली का उत्तर दिया है। प्रश्नावली के अपने उत्तर में पीपीसीएल ने घोषित किया है कि कंपनी ने सीधे और असंबद्ध विदेशी व्यापारियों अर्थात् एमबीके, एमएपी, कैमपार, ट्रेडकैम और रीवरज इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ निर्यात एमएपी द्वारा एक संबंधित आयातक अर्थात् मित्सुई एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया गया है जिन्होंने प्रश्नावली का अलग उत्तर नहीं दिया है। पीपीसीएल द्वारा एमएपी, एमबीके और कैमपार द्वारा बेची गई संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत और वह कीमत जिस पर एमएपी, एमबीके और कैमपार ने भारत को निर्यात किया है, की जांच, एमएपी, एमबीके और कैमपार द्वारा वहन किए गए संबंधित व्ययों पर विचार करने के बाद की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीपीसीएल ने भारत को पीओआई के द्वारा ***एम.टी पीयूसी का निर्यात किया है और उसमें से ***एम.टी, ***एम.टी का भारत को व्यापार की सहयोगी श्रृंखला के जरिए निर्यात किया गया है।
36. यह नोट किया जाता है कि एमएपी, एमबीके और कैमपार ने उनके द्वारा किए गए व्यय पर विचार करने के बाद लागत से अधिक कीमत पर उत्पाद का निर्यात किया है। किसी क्षतिपूर्ति करार या किसी अन्य कारण का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे उत्पादक की कीमत को अस्वीकृत करने और व्यापारी की कीमत अपनाने का कोई औचित्य हो। भारत को निर्यात की सभी व्यापार श्रृंखलाएं लाभप्रद पाई गई हैं, इसलिए प्राधिकारी ने पीपीसीएल अर्थात्

उत्पादक की कीमतों पर कारखाना द्वारा निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु विचार किया है। इसके अलावा, उत्पादक ने भारत को निर्यात के लिए कारखाना द्वारा व्यय के रूप में पोत परिवहन लागत, सर्वेक्षण लागत, संभलाई प्रभार, भंडारण लागत, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभार का दावा किया है। प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के अधीन पीपीसीएल के दावों को स्वीकार किया गया है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो व्यापारियों अर्थात् ट्रेड कैम इंटरनेशनल एफजैडई और रीवर ऐज ने पीओआई के दौरान भारत को निर्यातित उक्त ***एम.टी मात्रा हेतु अपेक्षित सूचना वाला निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (6क) और उपधारा(1) के स्पष्टीकरण (ख) तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के उपबंधों के अनुसार ***एम.टी के लिए निर्यात कीमत जिसके संबंध में अपेक्षित आवश्यक सूचना वाला उत्तर पूर्ण श्रृंखला के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पीपीसीएल हेतु निर्यात कीमत ऊपर यथाउल्लिखित समस्त निर्यात श्रृंखलाओं (सहयोगी तथा असहयोगी) पर विचार करने के बाद भारित औसत आधार पर विस्तृत सत्यापन के अधीन अंतिम आधार पर निर्धारित की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।

थाइलैंड से असहयोगी निर्यातक

38. थाइलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत प्रतिवादी निर्यातकों के निर्यात सौदों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

यूएसए के लिए निर्यात कीमत

39. यू एस ए से किसी निर्यातक/उत्पादक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। असहयोग के कारण प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस में दर्ज आयातों और नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार समायोजनों के आधार पर यूएसए से सभी निर्यातकों के लिए अंतिम रूप से निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

40. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु हेतु पाटन मार्जिन अंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

उत्पादक	सामान्य मूल्य/ सीएनवी	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(अम.डॉ./मी.ट.)	(%)	(रेंज)
पीपीसीएल, थाइलैंड	***	***	***	***	0-10
थाइलैंड से अन्य निर्यातक	***	***	***	***	10-20
यूएसए से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

41. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- चीन द्वारा एडीडी लागू करने के कारण देशों में अपने निर्यात भारत की ओर मोड़ दिए हैं।
- इस तथ्य के मद्देनजर कि कच्ची सामग्री के कारण लागत में किसी गिरावट के बिना या मामूली गिरावट के बावजूद प्रस्तावित पीओआई के दौरान फेनोल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से पीओआई के दौरान माह-वार विश्लेषण का अनुरोध किया जाता है।
- पीयूसी के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देशों से आयात पहले समग्र रूप से तथा उत्पादन और मांग की दृष्टि से कम हुए हैं और बाद में पीओआई में बढ़े हैं।
- आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।

- च. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग में मै. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन की शुरुआत से वृद्धि हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ती जा रही है।
- ज. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आई है और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में था।
- झ. पीओआई के दौरान पीबीआईजी और आरओसीई नगण्य रहे हैं।
- ञ. आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित हुई है।
- ट. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है।
- ठ. संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास अत्यधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं।
- ड. थाइलैंड ने पीयूसी के आयातों पर प्रतिबंध लगाए हैं और इस प्रकार, वैश्विक निर्यातों के लिए अपने बाजार को बंद कर दिया है, जिससे भारत एक लाभप्रद बाजार बन गया है।
- ढ. पाटन से इतिर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।
- ण. पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती हो रही है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में गिरावट आई है।
- त. पर्याप्त मांग की मौजूदगी के बावजूद आवेदकों को घाटे में निर्यात करना पड़ा है।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध :

42. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्यहितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
- क. अप्रैल से मई, 2019 में आयात की गई 12,009 मी. टन वस्तुओं, जो जांच की अवधि में स्टॉक में पड़ी हुई थी, के दावे के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
 - ख. आयातों की गणना के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई “समायोजन” की पद्धति अस्पष्ट, अपारदर्शी है और दोहरी गणना की गई है। इस कार्य पद्धति के अनुसार, जांच की अवधि के लिए आयातों में कमी आनी चाहिए थी लेकिन इसकीबजाय इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया रही है कि व्यापार उपचार जांचों में डीजीसीआईएंड एस और डीजीएसडाटा पर भरोसा किया जाए। यदि समायोजन का तर्क स्वीकार कर लिया जाए तो यह समस्या हर जांच में उत्पन्न होगी।
 - ग. घरेलू उद्योग ने भारत में भी फिनोल के आयातों के लिए रक्षोपाय जांच में आयातकी मात्रा के संबंध में अस्पष्ट और गलत अनुरोध किया था।
 - घ. निर्दिष्ट प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए किसी देश से सभी आयात सौदों को शामिल करने की है न कि केवल सकारात्मक सौदों के लिए ही है। घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार यहां तक कि यदि एक एकल सकारात्मक कटौती का सौदा है तो यह निर्धारण सौदों के आधार पर सकारात्मक होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यूरोपीयसमुदाय – ब्राजील से मैलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग के मामले में दिनांक 14 नवंबर, 2001 की डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग का यह दावा गलत है। यूरोपीय संघ (ईयू) ने कीमत कटौती के निर्धारण के लिए आयात के सौदों में कटौती पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने बिना कटौती वाली बिक्री के परिणामों की गणना की। दोनों गणनाओं के बीच का अंतर मामूली था और उससे निर्धारण पर प्रभाव पर्याप्त नहीं था। यह वर्तमान जांच में नहीं हो सकता और इसके अत्यधिक खराब परिणाम होंगे।
 - ड. घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण भी केवल ऐसे क्षतिकारी सौदों को शामिल करके ही किया जाना चाहिए अर्थात् जहाँपर पटुंच मूल्य एनआईपी से कम है। घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि यूरोपीय संघ, जो कम शुल्क नियम के सिद्धांत का भी अनुसरण करता है, गैर क्षतिकारी निर्यात सौदों को निकालने के बाद क्षति मार्जिन निर्धारित करता है। चूंकि इस प्रथा को डब्ल्यू टी ओ में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए प्राधिकारी को केवल ऐसे सौदों पर भी विचार करना चाहिए जो एन आई पी से कम है। घरेलू उद्योग ने कोठारी सूगर्स एंड केमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का हवाला दिया है। केवल इस कारण की वजह से कि इस प्रथा को अभी तक

डब्ल्यू टी ओ में चुनौती नहीं दी गई है, यह प्रथा स्वतः वैध नहीं हो जाती। पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन के आधार पर केवल तभी लगाया जा सकता है जब क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से कम हो। यदि घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए तो ऐसे कोई मामले नहीं होने चाहिए जहाँ क्षति मार्जिन निर्यातक के लिए शून्य शुल्क लगाकर नकारात्मक हो। क्षति मार्जिन से किसी भी अवांछित सौदे को अलग किए जाने से पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय संघ ने यह स्पष्ट किया था कि गैर क्षतिकारी आयातों को अलग करके निर्धारित किया गया कटौती का मार्जिन, कीमत कटौती के प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धतियों में से भी था। घरेलू उद्योग ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोठारी सूगर्स एंड केमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर गलत भरोसा किया है। माननीय न्यायाधिकरण ने इस मामले में ऐसा कोई व्यापक कानूनी कथन अथवा नियम निर्धारित नहीं किया है कि ऐसे आयात सौदे जो एन आई पी से अधिक हों, क्षति मार्जिन की गणना के प्रयोजन के लिए अलग किए जाने चाहिए।

- च. संबद्ध देशों से आयातों में निरपेक्ष अर्थों में अथवा भारत में खपत अथवा उत्पादन के लिए सापेक्ष रूप में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में भारी वृद्धि किए जाने को देखते हुए, संबद्ध आयात महत्वपूर्ण प्रकृति के नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यू एस ए, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, जापान और थाईलैंड ने चीन जन. गण. द्वारा मई, 2019 में एक अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अपने निर्यातों को चीन जन. गण. से हटाकर भारत की ओर रुख किया है। तथापि, आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि आयातों में मई, 2019 के बाद कमी आई है। चीन. जन. गण. द्वारा एक अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत में आ रहे आयातों को स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं किया है।
- छ. संबद्ध आयातों से कीमत में कटौती अप्रैल, 2018 से जून 19 (क) और जाँचकी अवधि (क) के लिए यू एस ए से आयातों के मामले में नकारात्मक थी, जो कीमत प्रभाव पर किसी भी दावे को नकारता है। इसके अलावा, आयात कीमतों में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के अनुरूप परिवर्तन आया है।
- ज. घरेलू बिक्री कीमतों में बिक्रियों की लागत में बदलाव के साथ उसके अनुरूप परिवर्तन हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में कीमतों में प्रतिबंध अथवा दबाव का कोई दावा नहीं किया जा सकता।
- झ. संगत आर्थिक पैरामीटर का एक विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, और बिक्री सहित लगभग सभी संगत आर्थिक पैरामीटरों में निष्पादन में सुधार दर्शाया है जैसा कि अद्यतन आवेदन और वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है।
- ट. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान अपने बाजार अंश में तेजी से वृद्धि कर रहा है।
- ठ. अकेले मै. दीपक फिनोलिक्स लि. के पास ही बाजार में करीब 55 प्रतिशत हिस्सा है। यह स्पष्ट है कि बाजार में संबद्ध आयातों का हिस्सा महत्वपूर्ण प्रकृति का नहीं होगा।
- ड. घरेलू उद्योग के समक्ष कर्मचारियों, मजूदरी, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता के संदर्भ में कोई हानि नहीं आई है।
- ढ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में घरेलू बिक्रियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन उसके द्वारा व्यय की गई अधिक व्याज और मूल्यहास लागतों से प्रभाव पड़ा है।
- ण. मै. दीपक फिनोलिक्स लि. को यदि कोई क्षति हुई है, तो वह स्टार्ट-अप की समस्याओं के कारण से है, जो वाणिज्यिक उत्पादन और अनुचित कीमत नीति शुरू होने में विलंब होने के कारण से है।
- त. मै. दीपक फिनोलिक्स द्वारा अपने निवेशक पत्राचार में प्रस्तुत रिपोर्ट में 'पाटित आयातों' का कोई उल्लेख नहीं है।
- थ. वर्ष 2018-19 में कोई कारणात्मक संबंध नहीं था, संबद्ध आयातों की मात्रा सबसे अधिक 123,727 मी. टन थी, लेकिन घरेलू उद्योग ने वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 में आयात की मात्रा की तुलना में जांच की अवधि (क) में आयात की मात्रा काफी कम है, तथापि, पीबीआईटी में जांच की अवधि (क) में घरेलू उद्योग के लिए गिरावट आई है।

- द. घरेलू उद्योग की आयात की मात्रा और लाभ संबंधी मापदंडों के बीच सह संबंध न होना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ध. यह विश्वास करने के लिए सशक्त प्रथमदृष्ट्या कारण है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा को बैलेंस शीट के संदर्भ में प्रकाशित अंतिम लेखों के वास्तविक आंकड़ों के साथ मान्य नहीं किया गया है जिससे कि एन आई पी, क्षति और कथित पाटन के दावे को मान्य किया जा सके।
- न. भारत में उत्पादकों में एक उत्पादक के बारे में यह जानकारी है कि वह अपने फिनोल का निर्यात हाल के समय में 750 यू एस डॉलर से भी कम कीमत पर कर रहा है और अभी भी बुनियादी सीमा शुल्क के संरक्षण के साथ तुलनीय अथवा जोड़ी गई समान कीमतों पर भारत में आयातों से क्षति होने का दावा करता है।
- प. कम से कम एक प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत अर्थात् बेनेजेन की कीमत के आधार पर एन आई पी का एक पारदर्शी निर्धारण होना चाहिए। आवेदकों द्वारा अपनाई गई वर्तमान कार्य पद्धति घरेलू उत्पादकों के पक्ष में एन आई पी को दर्शाती है और उपभोक्ता उद्योगों का नुकसान करती है। बेनेजीन की और पोलिप्रोपाइलीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें परिवर्तनीय हैं और हर समय न्यून स्तरों पर गिरती हैं।
- फ. प्राधिकारी द्वारा यू एस डॉलर में परिवर्तित करके एक संदर्भ कीमत अथवा एक निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाकर अपनाई गई कार्य पद्धति नियम 17(1)(ख) को अनुचित रूप से तोड़ मरोड़कर अपनाई गई है।
- ब. आवेदक ने निर्यातक देशों में फ्री डिस्पोजेबल क्षमताओं के संबंध में समर्थन में साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।
- भ. मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. की वार्षिक रिपोर्ट में कारणात्मक संबंध के रूप में उच्च ब्याज, मूल्यहास और कर्मचारी मजदूरी लागतों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि कंपनी ने फिनोल के लिए रिकार्ड उत्पादन हासिल किया है और यह कि भारत में फीडस्टॉक की कीमतें अन्य निर्यातक देशों की तुलना में अधिक हैं और भारतीय उत्पादन अधिक ओवरहेड लागतों के कारण प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसान में है।
- म. प्राधिकारी की संगत प्रक्रियाके अनुसार पर्याप्त क्षति संबंधी दावों की आशंका के लिए जांच की अवधि के प्रश्नात के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना है। तथापि, मै. दीपक फिनोलिक्स लि. की अद्यतन सूचना में पर्याप्त क्षति होने की कोई आशंका नहीं है। मै. दीपक नाइट्राइट लि. की लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के परिणामों में पीबीआईटी में 40.5 करोड़ से 63.60 करोड़ रूपए की 33 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। वर्ष दर वर्ष तुलना यह दर्शाती है कि पीबीआईटी और राजस्व 2018-2019 की तुलना में 2019-20 में लगभग दोगुना हो गए हैं। मै. दीपक फिनोलिक्स लि. के लिए कंपनी के समग्र बिक्री राजस्व में दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और समग्र लाभ में दूसरी तिमाही से चौथी तिमाही में काफी वृद्धि हुई है, जो पर्याप्त क्षति की आशंका को नहीं दर्शाता। हाल के आयात संबंधी डाटा भी अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक के वार्षिक आंकड़ों की तुलना में 2018-19 के लिए आयात की मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त क्षति/संभावित क्षति की निष्कर्षतः आशंका के प्रयोजन के लिए परिकलित सभी कारकों की मौजूदगी पर विचार किया जाए।
- य. आवेदकों द्वारा, मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. की 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग होने को देखते हुए क्षति के संबंध में समायोजन की पद्धति प्रदान की गई है, जो अपारदर्शी है और जो जानबूझकर अस्पष्ट दर्शाई गई प्रतीत होती है ताकि हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक टिप्पणी करने से रोका जा सके।
- र. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. के समक्ष जापान और थाईलैंड से एसिटीन के आयातों पर पाटनरोधी जांच में कच्ची सामग्री की उपलब्धता के संबंध में समस्या आई है।
- ल. यदि केवल घरेलू उद्योग का शेष सदस्य मै. दीपक फिनोलिक्स लि. है तो उसे पर्याप्त क्षति की बजाय पर्याप्त अवरोध आने का आरोप लगाना चाहिए था।
- व. समग्र क्षति अवधि की तुलना में केवल 2016-17 और 2017-18 के लिए डाटा के समायोजन के लिए कोई भी कारण प्रदान नहीं किए गए हैं। क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए आवेदकों ने मिले-जुले

- आंकड़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और 2016 को आधार वर्ष के रूप में लिया है, जबकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अन्य घरेलू उद्योग के सदस्यों के समक्ष हुई क्षति असंगत कारकों के संबंध में है।
- श. जबकि थाईलैंड से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी गिरावट आई है। थाईलैंड से आयातों की मात्रा का आवेदकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ष. सशक्त बिक्री और लाभप्रदता के निष्पादन के चलते इन्वेन्ट्री के संबंध में दावे पर्याप्त नहीं हैं।
- स. सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित एक अनिवार्य बी आई एस प्रमाणन की आवश्यकता भविष्य में बढ़ते आयातों के संबंध में एक निवारक के रूप में कार्य करेगी।
- ह. आवेदकों ने अप्रैल-जून, 2019 में लाभप्रदता में अपनी सबसे अधिक गिरावट देखी है, यह ऐसी अवधि है, जिसमें थाईलैंड के लिए कीमत कटौती नकारात्मक थी। इस प्रकार से, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे थाईलैंड से कीमत कटौती होने को आवेदकों के लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट होने से जोड़ा जा सके।
- क्ष. प्राधिकारी को मैसर्स हिन्दुस्तान ऑगेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड के खराब निष्पादन की जांच करनी चाहिए और यह देखा चाहिए कि मैसर्स हिन्दुस्तान ऑगेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड को हुई कोई कथित क्षति उनकी अपनी अक्षमताएं जारी रहने के कारण से है न कि इसका कारण संबद्ध आयातों का होना है।
- त्र. कथित कटौती और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध में एक बाधा है। साथ ही आवेदक केवल इस प्रकार की अटकलबाजी के अलावा कोई तर्क देने में विफल रहे हैं कि थाईलैंड से आयात प्रतिबंधों से भारत में अधिक आयात हो रहे हैं।
- ज. शुल्क लागू रहने के बावजूद भारतीय उद्योग को निरंतर क्षति होते रहना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति बाह्य कारकों की वजह से है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

43. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से किया गया क्षति के संबंध में यह विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का निपटान करता है।

ज.3.1 संचयी मूल्यांकन

44. नियमावली के अनुलग्नक-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से कोई उत्पाद आयात किया जाता है, उनकी भी पाटनरोधी जांच की जाती है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि:-
- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, जिसे निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो साझा आयात समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता है, और
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।
45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-
- क. संबद्ध वस्तुएं भारत में संबद्ध देशों से पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देशों से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात में न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा होती है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा होती है। यह नोट किया जाता है कि ऐसे उपभोक्ता, जो घरेलू उद्योग से खरीद कर रहे हैं, वे संबद्ध देशों में से भी आयात कर रहे हैं।

46. जहाँ तक नियमावली के अनुलग्नक-II के पैरा (iii) के मामले का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात अनुलग्नक-II के पैरा (iii) के मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। अतः संचयी मूल्यांकन के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह मत सही नहीं है।
47. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझा है।
48. नियमावली के अनुलग्नक-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकती है, ".....पाटित आयातों की मात्रा सहित सभी संगत तथ्यों, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव को ध्यान में रखते हुए.....।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जाँच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा मंद करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, इन्वेन्ट्री, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि जैसे उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले सूचकांकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के अनुसार विचार किया गया है।
49. आयात की मात्रा और कीमतों के संबंध में, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस की आयात संबंधी सूचना और थाईलैंड से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर भरोसा किया है।
50. प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार, कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सभी आयात संबंधी सौदों को शामिल किया गया है।
51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. का वर्ष 2016-17 और 2017-18 में बहुत ही कम उत्पादन था। कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि इसका कारण कंपनी के समक्ष आई महत्वपूर्ण कार्यशील पूंजी की समस्याएं आना था। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कम उत्पादन करने के कारण देश में पाटन होना नहीं था और ये "अन्य कारकों" के कारण था। अतः प्राधिकारी ने जांच की अवधि में हासिल की गई क्षमता के उपयोग को देखते हुए लाभ, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल के संबंध में हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. के निष्पादन का मूल्यांकन किया है।
52. इस उठाए गए मुद्दे के संबंध में कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत डाटा को बैलेंस शीट के संदर्भ में प्रकाशित अंतिम लेखों पर वास्तविक आंकड़ों के साथ मान्य नहीं किया गया है और इसे एन आई पी, क्षति और कथित पाटन पर दावे को मान्य नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने विस्तृत सत्यापन किए जाने की शर्त पर अनंतिम आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है और उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के प्रस्तुत की गई सूचना को विस्तृत सत्यापन किए जाने की शर्त पर अनंतिम रूप से स्वीकार भी कर लिया गया है।
53. इस तर्क के संबंध में कि आयातों की गणना के लिए घरेलू उद्योगों द्वारा अपनाई गई 'समायोजन' की पद्धति अस्पष्ट, अपारदर्शी है और इससे दोहरी गणना हुई है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और इसकी कीमतों को डीजीसीआई एंड एस डाटा और संबद्ध देशों से उत्पादक तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से निर्धारित किया गया है।
54. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति होने के कारणों में अन्य कारण हैं और घरेलू उद्योग के संघटकों की वार्षिक रिपोर्ट में दिए विवरणों के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यहां किया गया क्षति विश्लेषण यह प्रमाणित करने के लिए स्वतः स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
55. क्षति विश्लेषण के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के सभी अन्य अनुरोधों को निम्नलिखित पैरा में शामिल किया गया है।

ज.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**क) मांग का मूल्यांकन**

56. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँचके प्रयोजन से भारत में उत्पादन की मांग को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों को मिलाकर विचार किया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	364	364	572	572
संबद्ध आयात	मी. टन	110,557	108,800	146,446	117,157	43,705	87,410
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	106	106	79	79
पाटनरोधी शुल्क आयात	मी. टन	98,657	105,275	68,332	54,665	17,283	34,566
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	55	55	35	35
अन्य देशों से आयात	मी. टन	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	63	63	8	8
कुल मांग	मी. टन	324,477	34,215	465,481	372,385	185,634	371,268
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	115	115	114	114

57. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि जाँचकी अवधि में एक मामूली गिरावट के साथ है। संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग में जाँच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष अर्थों में अथवा उत्पादन के संबंध में अथवा भारत में खपत के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
संबद्ध देश	मी. टन	1,10,557	1,08,800	1,46,446	1,17,157	43,705	87,410
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	106	106	79	79
थाईलैंड	मी. टन	57,688	87,568	96,022	76,818	30,749	61,498
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	133	133	107	107
यू एस ए	मी. टन	52,869	21,232	50,424	40,339	12,956	25,912
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	76	76	49	49

पाटनरोधी शुल्क वाले देश	मी. टन	98,657	1,05,275	68,332	54,665	17,283	34,566
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	55	55	35	35
अन्य	मी. टन	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	63	63	8	8
कुल आयात	मी. टन	2,81,874	2,88,087	2,71,806	2,17,445	63,813	1,27,626
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	77	77	45	45
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात							
कुल आयात	%	39	38	54	54	68	68
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	137	137	175	175
भारतीय उत्पादन	%	254	203	72	72	34	34
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	28	28	13	13
भारतीय मांग	मी. टन	34	32	31	31	24	24
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	92	69	69

59. यह पाया गया है कि :-

- क. आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध आयातों की समग्र मात्रा में निरपेक्ष दृष्टि से और जांच की अवधि में देश में उत्पादन और खपत के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि आयातों में यह गिरावट भारतीय मांग की 54 प्रतिशत तक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के सामान्य परिणामों के कारण थी। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि समग्र आयातों में गिरावट देश में क्षमताओं में ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि होने के सामान्य परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति में थी कि जहां देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मांग आपूर्ति अंतराल था। वर्तमान जांच की अवधि के दौरान 3.71 लाख मी. टन की स्थापित मांग की तुलना में दीपक फिनोलिक्स लि. द्वारा उत्पादन की शुरुआत किए जाने से पूर्व देश में संस्थापित क्षमता केवल 76,750 मी. टन थी।
- ख. भारत में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जबकि संबद्ध आयात 2016-17 और 2017-18 में भारत में कुल आयातों के 40 प्रतिशत से कम थे, उसके हिस्से में अप्रैल, 2018 से जून, 2019 की अवधि में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और उसके बाद वर्तमान जांच की अवधि में 68 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत में अधिकांश आयात में संबद्ध देशों से आयात शामिल हैं।
- ग. तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में देश में उत्पादन और खपत के संबंध में गिरावट आई है।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा मंद करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमतों पर प्रतिबंध और कीमतों में मंदी, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) और एन आई पी की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

61. कीमत कटौती विश्लेषण करने के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती के प्रभाव इस प्रकार हैं :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
संबद्ध देश				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
निवल बिक्री वसूली	रू./मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच मूल्य	रू./ मी. टन	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	152	152	108	108
कीमत कटौती	रू./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	20-30	20-30	(0)-(10)	(0)-(10)	0-10	0-10

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
थाईलैंड				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
निवल बिक्री वसूली	रू./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच मूल्य	रू./ मी. टन	69,264	73,139	1,01,345	1,01,345	69,574	69,574
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	146	146	100	100
कीमत कटौती	रू./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25	20-30	(0)-(10)	(0)-(10)	0-10	0-10

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
यू एस ए				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
निवल बिक्री वसूली	रू./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच मूल्य	रू./ मी. टन	60,813	70,371	95,295	95,295	72,085	72,085
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	157	157	119	119
कीमत कटौती	रू./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	30-40	20-30	(0)-(10)	(0)-(10)	(0)-(10)	(0)-(10)

62. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख) कीमतों का दमन और मंदी

63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में मंदी आ रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का कारण महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का दमन करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा नहीं होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन को रोकना है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
बिक्रियों की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	113	113	96	96
बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
पहुंच मूल्य	रु./ मी. टन	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	152	152	108	108

64. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में अप्रैल, 2018 – जून, 2019 तक वृद्धि हुई, उसके बाद उसमें गिरावट आई है। तथापि, आयातों की बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत का दमन हुआ। यह भी नोट किया जाता है कि एक ओर जहाँ आयातों की पहुंच कीमत 2016-17 और 2017-18 में उत्पादन की लागत से कम थी, यह अप्रैल, 2018 – जून, 2019 में उत्पादन की लागत से काफी अधिक थी। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत में जाँच की अवधि में उत्पादन की लागत से कम गिरावट रही। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के चलते बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आ रही है।

ग) कम कीमत पर बिक्री

65. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग के समक्ष कम कीमत पर बिक्री की समस्या आने की भी जाँचकी है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए औसत एन आई पी के आधार पर निर्धारित गैर-क्षति कीमत (एन आई पी) की डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों से प्राप्त आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।
66. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की गैर क्षति कीमत से कम थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण जाँचकी अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री का सामना किया है।

विवरण	इकाई	थाईलैंड	यू एस ए	संबद्ध देश
आयात की मात्रा	मी. टन	30,749	12,956	43,705
पहुंच मूल्य	यूएस डॉलर/ मी. टन	970.81	1,005.85	981.19
एनआईपी	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री मार्जिन	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज % में	0-10	0-10	0-10

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

67. नियमावली के अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और भेदभाव रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए,

जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, व्यय क्षमता, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्रियों, रोजगार मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंड नीचे दिए गए हैं :-

68. प्राधिकारी ने अपने अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की उद्देश्यपरक जाँच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन बिक्रियां और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
क्षमता	मी. टन	76,750	76,750	3,45,938	2,76,750	2,76,750	2,76,750
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	361	361	361	361
उत्पादन	मी. टन	43,524	53,490	2,02,461	1,61,969	1,29,280	2,58,560
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	372	372	594	594
क्षमता उपयोग	%	57	70	88	88	93	93
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	156	156	165	165
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	42,604	53,129	1,93,675	1,54,940	1,21,821	2,43,642
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	364	364	572	572

70. घरेलू उद्योग के पास संस्थापित क्षमता में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह फिनोल के लिए 2,00,000 मी. टन की एक संस्थापित क्षमता और दीपक फिनोलिक्स द्वारा 1,20,000 मी. टन की संस्थापित क्षमता के साथ 1200 करोड़ रुपये के सकल निवेश पर एक नए संयंत्र की स्थापना होने के कारण से है। संयंत्र ने नवम्बर, 2018 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। देश में संस्थापित क्षमता 76,750 मी. टन थी, जबकि मांग 3 लाख से अधिक की थी। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह निवेश देश में उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग – आपूर्ति अंतराल पर विचार करते हुए न्यायोचित था।

71. घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण नई क्षमता की स्थापना के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ii. मांग में बाजार अंश

72. घरेलू उद्योग के बाजार अंश को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
घरेलू उद्योग	%	13.13	15.57	41.61	41.61	65.62	65.62
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	317	317	500	500

संबद्ध देश	%	34.07	31.89	31.46	31.46	23.54	23.54
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	92	69	69
पाटनरोधी शुल्क वाले देश	%	30.40	30.85	14.68	14.68	9.31	9.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	48	48	31	31
अन्य देश	%	22.39	21.69	12.25	12.25	1.52	1.52
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	55	55	7	7
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

73. यह नोट किया जाता है कि :-

- क. घरेलू उद्योग का बाजार में पहले बहुत ही कम हिस्सा था। ऐसा देश में उत्पादन क्षमताएं न होने और हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. द्वारा कार्यशील पूंजी की कमी के चलते उत्पादन में कमी किए जाने के कारण से था।
- ख. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. द्वारा एक तर्कसंगत स्तर तक पुनः उत्पादन शुरू किए जाने और दीपक फिनोलिक्स लि. द्वारा अपने नए संयंत्र में उत्पादन आरंभ किए जाने के साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री में काफी वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ग. जबकि विभिन्न स्रोतों से आयातों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई, जहां तक संबद्ध देशों का संबंध है, अप्रैल-जून, 2019 में बाजार अंश में गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि बाजार अंश में वृद्धि को नई क्षमताओं में वृद्धि होने की सच्चाई के साथ-साथ भी देखा जाना चाहिए और जिस कीमत पर घरेलू उद्योग उत्पाद की बिक्री कर रहा है, उसे भी देखा जाना चाहिए।

iii. वस्तु सूचियां (इन्वेंट्री)

74. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास वस्तु सूचियों (इन्वेंट्री) की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
शुरूआत में	मी. टन	***	***	***	***	***	***
अंत में	मी. टन	***	***	***	***	***	***
औसत	मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	340	340	556	556

75. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत इन्वेंट्री में क्षति अवधि के बाद पर्याप्त वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल नीचे तालिका में दर्शाई है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
बिक्रियों की लागत	रु/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	113	113	96	96
बिक्री कीमत	रु/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	114	87	87
प्रति इकाई लाभ	रु/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	120	120	(8)	(8)
कुल लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	567	567	(61)	(61)
नकदी लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	621	621	127	127
ब्याज पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	360	360	159	159
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	26	26	13	13

77. यह देखा गया है कि :-

- क. घरेलू उद्योग अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक लाभ अर्जित कर रहा था। जबकि अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक प्रति इकाई लाभ में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद उसमें इतनी गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा।
- ख. नकदी लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में भी लाभ की तरह की प्रवृत्ति रही। अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक नकदी लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि तक गिरावट रही।
- ग. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पूरी जांच की अवधि के दौरान जारी रही। यह नोट किया जाता है कि लाभ, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट रही है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

78. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019		पीओआई	
				वास्तविक	वार्षिक	वास्तविक	वार्षिक
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	156	156	212	212
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	188	188	223	223
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन /प्रतिदिन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	372	372	594	594

79. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सुधार आया है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को दर्शाने के लिए संगत नहीं हैं।

vi. विकास

80. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभ, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल के संदर्भ में विकास नीचे तालिका में दिया गया है :-

विवरण	इकाई	2017-18	अप्रैल, 2018-जून, 2019 (क)	पीओआई
उत्पादन	वाई/वाई	23	203	60
घरेलू बिक्रियां	वाई/वाई	25	192	68
क्षमता उपयोग	वाई/वाई	23	27	6
औसत इन्वेंट्री	वाई/वाई	10	210	64
घरेलू उद्योग का बाजार अंश	वाई/वाई	19	167	58
लाभ/हानि	वाई/वाई	(10)	526	(111)
नकदी लाभ	वाई/वाई	(12)	606	(79)
पीबीआईटी	वाई/वाई	(3)	273	(56)
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	वाई/वाई	(20)	(68)	(51)

81. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का विकास मात्रा संबंधी मापदंडों (उत्पादन और बिक्रियों) के संबंध में सकारात्मक रहा और कीमत संबंधी मापदंडों (बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत, लाभ और निवेश पर प्रतिफल) के संबंध में सकारात्मक रहा।

vii. पाटन मार्जिन की मात्रा

82. पाटन का मार्जिन भारत में पाटित किए जा रहे आयातों को देखते हुए एक संकेतक है। जांच में यह दर्शाया गया है कि जाँचकी अवधि के पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

viii. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

83. विचाराधीन उत्पाद में हाल ही में महत्वपूर्ण निवेश किया गया था। घरेलू उद्योग जांच की अवधि में वित्तीय हानि का सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही प्रतिस्पर्धा के साथ, जो कि पाटित आयातों के कारण से है। उद्योग का प्रचालन प्रभावित हुआ है, जिससे पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को केवल उत्पाद के निष्पादन के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

84. आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों के सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत न केवल इसकी निवल बिक्री कीमत से कम है बल्कि घरेलू उद्योग की एन आई पी से भी कम है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आई है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है। तीसरे देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से या तो पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है या न्यूनतम है या अधिक कीमतों पर है। पाटित आयातों से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार से अंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात आना है।

ज.3.4. क्षति मार्जिन

85. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुलग्नक-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षति कीमत (एन आई पी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षति कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ें अपनाए

गए हैं और इन्हें जांच की अवधि के लिए पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए गैर क्षति कीमत पर विचार किया गया है। यूटिलिटी के साथ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किए जाने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर-आवृत्ति व्यय शामिल नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसतन निवल निर्धारित परिसम्पत्तियां और औसतन कार्यशाली पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर से पूर्व कर) की अनुमति पूर्व कर लाभ के रूप में दी गई थी ताकि नियमावली के अनुलग्नक - III में यथा निर्धारित गैर क्षति कीमत निकाली जा सके और इसका अनुसरण किया जा रहा है।

86. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
87. प्राधिकारी द्वारा पहुंच कीमत और उपरोक्त निर्धारित गैर क्षति कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

देश	उत्पादकों/निर्यातकों का नाम	गैरक्षति कीमत (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पहुंच मूल्य (यूएस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
थाईलैंड	पीटीटी फिनोल कंपनी लि.	***	***	***	***	0-10
थाईलैंड	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	10-20
यूएसए	सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	0-10

ज.3.5 क्षति संबंधी निष्कर्ष

88. घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पाद और निष्पादन के आयातों की जांच स्पष्ट तौर पर यह दर्शाती है कि :-

- संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है।
- यद्यपि बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत दोनों में ही जाँचकी अवधि के दौरान गिरावट आई है, लेकिन आयातों की बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों का दमन हो रहा है।
- संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आई है।
- यद्यपि उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में वित्तीय हानि का सामना किया है।

89. इसे देखते हुए प्राधिकारी का अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है।

झ. गैर-संबद्धता का विश्लेषण

90. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जाँचकी है, जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण से न हो। ऐसे कारक, जो इस संबंध में संगत हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी, अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच मुकाबला, प्रौद्योगिकी में बदलाव और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। प्राधिकारी ने यह जाँचकी कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक को हुई क्षति अन्य कारकों से है न कि संबद्ध देश से आयातों के कारण से है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो यह स्थापित कर सके कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण क्षति हुई

है। यहाँ तक कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे मात्र अनुमान हैं जिनकी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर जांच की गई है।

क) पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

92. अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है अथवा न्यून हैं अथवा अधिक कीमतों पर हो रहे हैं। यद्यपि सऊदी अरब से आयातों की मात्रा नगण्य से अधिक है, लेकिन क्षति अवधि और जाँचकी अवधि के दौरान आयातों का पैटर्न यह दर्शाता है कि आयातों में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान आयात केवल एक माह में हुए हैं। इस प्रकार अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती प्रतीत नहीं हो रही।

ख) मांग में कमी

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि देश में पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

94. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, खपत के पैटर्न में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाएं

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाएं घरेलू उद्योग को क्षति के दावे के लिए जिम्मेदार हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में बदलाव

96. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में पर्याप्त परिवर्तन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो।

च) उत्पादकता

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। अतः घरेलू उद्योग को इस संबंध में क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

98. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु डाटा पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

99. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षति काडाटा प्रदान किए हैं और इन्हें प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से स्वीकार कर लिया गया है। अतः उत्पादित अन्य उत्पादों और आवेदक द्वारा बेचे गए उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कोई संभव कारण नहीं है।

कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

100. प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण है।

- क. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और यह घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर हो रही है।
- ख. आयातों के कारण घरेलू उद्योग उत्पाद को उत्पादन की लागत से कम कीमत पर बेचने को मजबूर है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण कीमतों में मंदी का सामना करना पड़ा है।
- ग. आयात कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।
- घ. बिक्री कीमत और उसके लाभों में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को नकदी लाभ और अर्जित निवेश प्रतिफल में गिरावट आई।

101. इस प्रकार प्राधिकारी यह अनंतिम निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य लाभ

102. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों के कारण कमी नहीं आएगी। इसके प्रतिकूल पाटनरोधी उपायों के कारण पाटन प्रक्रियाओं के चलते प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट में रुकावट आएगी और संबद्ध वस्तुओं के ग्राहकों को व्यापक विकल्प की उपलब्धता में मदद मिलेगी। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के चलते घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों के कारण संबद्ध देशों से आयातों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं होगा और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

103. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
- क. संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर निर्यात की गई हैं।
- ख. घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग के समक्ष पर्याप्त क्षति की समस्या पाटित आयातों के कारण है।
104. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के लिए जांच शुरू किए जाने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति को दूर करने, जांच पूरी होने में विलंब को देखते हुए अनंतिम शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
105. नियमावली के नियम 4(घ) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में जो कम हो, के समान अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके। मामले की तथ्यता को देखते हुए और प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क के बेंचमार्क/संदर्भ रूप की सिफारिश करना उपयुक्त समझा गया है। पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित संदर्भराशि और केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाए जाने वाले पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के समान होगा।
106. प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत यथानिर्धारित आकलनयोग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	290711	फेनाल	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई अन्य देश	पीटीटी फिनोल कंपनी लि.	989.36	मी.ट.	अम.डॉ.

2	290711	फेनाल	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई अन्य देश	क्र.सं. 1 से इतर अन्य कोई उत्पादक	992.58	मी.ट.	अम.डॉ.
3	290711	फेनाल	उन देशों से इतर कोई अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	थाइलैंड	कोई	992.58	मी.ट.	अम.डॉ.
4	290711	फेनाल	यू एस ए	यू एस ए	कोई	1,006.96	मी.ट.	अम.डॉ.
5	290711	फेनाल	उन देशों से इतर कोई अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	यू एस ए	कोई	1,006.96	मी.ट.	अम.डॉ.

ड. आगे की प्रक्रिया

107. प्रारंभिक जाँचपरिणाम अधिसूचित करने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

- क. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जाँचपरिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत पाए जाने पर अंतिम जाँचपरिणामों में विचार किया जाएगा।
- ख. घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो इससे संबंधित हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अलग से भेजा जा रहा है, जो अपने विचारों से इन प्रारंभिक जाँच परिणामों को प्रकाशित करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अवगत कराएंगे।
- ग. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जाँचपरिणामों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
- घ. प्राधिकारी सभी पक्षों को जाँचके लिए अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए नियम 6 (6) के संदर्भ में मौखिक सुनवाई करेगा।
- ड. मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जाँच परिणामों में जाँचकी जाएगी।
- च. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।
- छ. प्राधिकारी आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन करेंगे।
- ज. प्राधिकारी अंतिम जाँचपरिणामों की घोषणा करने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION
PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 20th August, 2020

Case No. ADD-(OI) 02/2020

Subject : Preliminary Findings of Anti-dumping Investigation concerning imports of "Phenol" into India originating in or exported from Thailand and United States of America.

F. No. 6/3/2020-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

- (1) M/s. Deepak Phenolics Ltd., M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. and M/s. SI Group India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the "Applicants") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as "the Authority") in accordance with the Customs Tariff

Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Rules”) for imposition of anti-dumping duty (ADD) on imports of “Phenol” (hereinafter also referred to as the “Product under Consideration” or “PUC” or “subject goods”) from Thailand and United States of America (USA) (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide notification No. 6/3/2020-DGTR dated 25th February, 2020, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of ADD, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 25th February, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 25th February, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations, the Domestic Industry, and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicants. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 4th April, 2020, the time was extended up to 24th April 2020. Vide communication dated 23rd April, 2020, the time was extended up to 10th May, 2020 and vide communication dated 11th May, 2020, the time was further extended up to 20th May, 2020. Any submission made by interested parties even after the due date has been taken into account to the extent considered relevant and appropriate for the purpose of present preliminary determination. Further, the Authority shall consider all submissions made by interested parties during the course of present investigations at the time of final determination.
 - g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s. PTT Phenol Company Limited, Thailand;
 - ii. M/s. Deckota Gasification Company, USA;
 - iii. M/s. Dow Chemical Co., USA;
 - iv. M/s. Georgia Gulf, USA;

- v. M/s. Shell Chemicals, USA;
 - vi. M/s. AdvanSix, USA;
 - vii. M/s. INEOS Phenol, USA.
- h. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted exporter's questionnaire responses:
- i. M/s. PTT Phenol Company Limited (PPCL), Thailand;
 - ii. M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP), Singapore;
 - iii. M/s. Mitsui & Co. Ltd. (MBK), Japan;
 - iv. M/s. Kempar Energy Pte. Ltd. (Kempar), Singapore.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s. C.J.Shah and Company;
 - ii. M/s. Haresh Kumar & Co.;
 - iii. M/s. PCL Oil & Industries;
 - iv. M/s. KantilalManilal& Co. Pvt. Ltd.;
 - v. M/s. Sonkamal Enterprises;
 - vi. M/s. Khetan Brothers;
 - vii. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited;
 - viii. M/s. Acron Enterprises;
 - ix. M/s. Naiknavare Chemicals Limited;
 - x. M/s. Paras Dyes & Chemicals;
 - xi. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited;
 - xii. M/s. United Phosphorus Ltd.;
 - xiii. M/s. Resins & Plastic Ltd.;
 - xiv. M/s. Kailash Polymers;
 - xv. M/s. Centrum MetalicsPvt. Ltd.;
 - xvi. M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.;
 - xvii. M/s. Meghdev Enterprises;
 - xviii. M/s. Satguru International;
 - xix. M/s. High Polymer Labs Ltd.;
 - xx. M/s. Rainbow Colours & Chemicals;
 - xxi. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.;
 - xxii. M/s. Karmen International (P) Ltd.;
 - xxiii. M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.;
 - xxiv. M/s. NGP Industries Ltd.;
 - xxv. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd.;
 - xxvi. M/s. India Glycols Ltd.;
 - xxvii. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.;
 - xxviii. M/s. National Plywood Industries Ltd.;

- xxix. M/s. Kundan Rice Mills Ltd.
- j. In response to the above notification, following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses:
- i. M/s. Aica Laminates India Private Limited;
 - ii. M/s. Greenlam Industries Limited;
 - iii. M/s. Clean Science & Tech Pvt. Ltd.;
 - iv. M/s. Meghmani Organics Ltd.;
 - v. M/s. Akin Chemicals Pvt. Ltd.;
 - vi. M/s. Atul Ltd.;
 - vii. M/s. Virgo Laminates Ltd.
- k. The following parties have filed legal submissions in response to the initiation notification:
- i. M/s. Clean Science & Tech Pvt. Ltd.;
 - ii. Meghmani Organics Ltd.;
 - iii. Akin Chemicals Pvt. Ltd.;
 - iv. Haresh Petrochem Pvt. Ltd.;
 - v. Gitanjali Chemicals Pvt. Ltd.;
 - vi. Atul Ltd.;
 - vii. Cent Ply.
- l. The Authority sent a copy of the initiation notification to the following known Associations of the subject goods in India:
- i. Indian Laminate Manufacturer's Association,
 - ii. The Institute of Indian Foundrymen.
- However, none of the user Associations responded to the initiation notification.
- m. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- n. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st July, 2019 to 31st December, 2019 (6 months). The injury examination period has been considered as the period from 1st April, 2016-31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018, 1st April, 2018-30th June, 2019 and the period of investigation.
- o. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DGS) for subject goods for the injury period, including the POI, and analysed the data after due examination of the transactions.
- p. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) based on the cost of production and reasonable profits to sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the Domestic Industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q. The information provided by the Applicant was examined by the Authority by way of a table study, to the extent deemed necessary. Only such information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of preliminary findings.
- r. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as

confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- s. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of facts available.
- t. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported by evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- u. ‘***’ in this preliminary finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- v. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹71.67.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

“The product under consideration in the present investigation is “Phenol”. The product is marketed in two forms i.e. bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed sales can be of much smaller container loads and are generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.

This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

C.1 Submissions of the Domestic Industry

5. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- a. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.
 - b. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11.
 - c. The goods produced by the Applicant are like article to the product under consideration imported from subject countries as they are comparable in terms of chemical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject country. The Applicants have produced like article to the imported products.

C.2. Submissions of other interested parties

6. No submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties regarding product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is “Phenol”.
8. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk (in loose) and packed. Bulk sales are normally in loose

form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc.

9. The product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
10. It has been noted from the information available on record that the product produced by the Domestic Industry is like article to product under consideration imported from subject countries. The product produced by the Domestic Industry, and subject goods imported from subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The contention of the Applicant has not been disputed by the other interested parties. The Authority provisionally holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the Domestic Industry

11. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the scope of Domestic Industry and standing:
 - a. The Applicants, namely, Deepak Phenolics Ltd., Hindustan Organics Chemicals Ltd. and SI Group India Pvt. Ltd., constitute 100% of the domestic production for the subject goods in India.
 - b. The Applicants have not imported the subject goods in the POI from the subject countries.
 - c. The Applicants are not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.

D.2 Submissions of other interested parties

12. No submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties regarding scope and standing of Domestic Industry.

D.3. Examination by the Authority

13. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines Domestic Industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

14. The Application has been jointly filed by Deepak Phenolics Ltd., Hindustan Organics Chemicals Ltd. and SI Group India Pvt. Ltd. The Applicants account for 100% of Indian production, as there is no other producer of the subject goods in India, apart from the Applicants. The Applicants have claimed that neither they have imported the PUC from the subject countries in the POI nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
15. Accordingly, the Authority holds that the Applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions of the Domestic Industry**

16. The Applicants have submitted that information otherwise available in the public domain has been claimed as confidential by PPCL and MBK in the exporters' questionnaire responses. Further, the exporters have claimed excessive confidentiality in excess of the provisions of the Authority's Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018. MBK has not submitted Part IV of the exporters' questionnaire response.

E.2. Submissions of other interested parties

17. The exporters, importers, users and other interested parties have submitted that the Applicants have claimed excessive confidentiality and have not fulfilled the guidelines prescribed in the Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018.
18. If the Applicants have made arguments on retrospective imposition in the confidential version of the application, it is a clear violation of confidentiality provisions, since the same has not been provided in the non-confidential version. The inability of the Applicants to provide the arguments in non-confidential version hinders the ability of the interested parties to provide meaningful comments on the same and defend their interests on this crucial issue.

E.3. Examination by Authority

19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

20. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
21. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
22. As regards the arguments of retrospective imposition of duties not in the non-confidential version of the application, it is noted that Applicants requested for imposition of retrospective form of duties through letters filed after the filing of application. The non-confidential versions of the letters have been circulated by the Applicants to all interested parties.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**F.1. Submissions by the Domestic Industry**

23. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to various issues:

- a. The parameters laid down under the law for retrospective imposition of duty are fully met in the present case. It is vital to consider (a) imposition of ADD on a retrospective basis; and (b) import assessments are made provisional pending outcome of the investigation.
- b. Since there is significant intensified injury within POI, which intensified further in post POI, the Domestic Industry has requested the Authority to consider imposition of benchmark form of duty in order to address the intensified injury.

F.2. Submissions of other interested parties

24. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to various issues:

- a. The Applicants have not made any arguments requesting for the imposition of retrospective ADD in the application. No documents in the public file show such arguments either.
- b. There is no requirement to levy ADD retrospectively. The basic principle of taxation law is certainty and predictability for the tax-payer and, therefore, taxes and duties are prospective in nature. Retrospective imposition is against the norm in ADD as well. It causes prejudice to the bona-fide importer and the user. Section 9A(3) of the Act merely carves out an exception for rare and extraordinary situations with conditions, (a) history of dumping and (b) massive dumping in short period of time. No evidence has been provided by Applicants to substantiate the claim. The 'history of dumping' should be specific to the countries against whom the investigation is ongoing. Retrospective duty has been requested by the DI in multiple investigations, however, no such duty was imposed by the Authority, showcasing clear that it is a provision which mandates extraordinary conditions to exist and must be used. The DI has not established the extraordinary circumstances. The Authority has to ascertain the fulfilment of the requisite conditions prior to the recommendation of a retrospective levy of duty. The onus to prove that the conditions are met lies upon the Applicants and the non-confidential petition does not provide any averments.
- c. The Authority has not provided any reasons for adopting such a short POI, and the initiation notice is, therefore, in clear violation of the Rules. The Authority has consistently rejected shorter POI in multiple investigations previously and initiated investigations on POI longer than the POI proposed by the Applicants.
- d. M/s. Deepak Phenolics Ltd. must be facing start up difficulties and technical problems. The plant was also shut due to internal reasons.
- e. There is no further requirement to conduct one more anti-dumping investigation to assess dumped imports of Phenol and material injury or threat of material injury to the Domestic Industry. The Authority has conducted many anti-dumping investigations on Phenol in the last 17 years. In 2019, M/s. Deepak Phenolics Ltd. had approached the Authority for imposing Safeguard duty on Phenol which was later withdrawn by them. M/s. Deepak Phenolics Ltd. had filed an application for inclusion of product phenol in the Restrictive list of Imports. However, the same was dismissed by the Ministry of Chemicals.
- f. The user industry is dependent on imports as there is a demand-supply gap for Phenol in India.
- g. The Applicants have failed to provide any compelling reasons for the Authority to conduct a monthly analysis. The DGTR Manual prescribes scenarios where such an analysis may be undertaken where there are wide variations in cost of production due to raw material price fluctuations. As acknowledged, there is insignificant decline in raw material prices. For a monthly dumping assessment, monthly cost data has to be called, which is an expansive exercise. The Authority may kindly issue an official notification and thereafter provide time for such information. The exercise has to be done prior to provisional findings.

F.2. Examination by the Authority

25. The Authority has considered the views of the interested parties, as follows-

- a. The issue of retrospective imposition of ADD is required to be considered in the final determination. The Authority shall consider submissions of all interested parties while deciding the issue.
- b. Regarding selection of 6 months as POI, the Authority notes that the adoption of 6 months as POI is not inconsistent with the Rules, provided the Applicants substantiate the need for such a time period, and the same is accepted by the Authority. In this case, the Applicants substantiated the need for considering 6 months as the POI by providing reasons that dumping commenced in this period and the injury to the Domestic Industry intensified during the POI. The Applicants claimed that the six months POI is appropriate in view of the fact that China PR had imposed ADD on subject countries in May 2019, which has led to a significant drop in import prices from subject countries to India. The product was exported at a much higher price in the month of April and May, 2019. Thus, the inclusion of April and May, 2019 would have implied inclusion of a “period of no dumping”. It would not be appropriate to fix a period for which there is no allegation of dumping.
- c. The arguments submitted by the Applicants were examined by the Authority. It is noted that the purpose of an AD investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the Domestic Industry. It is further noted that the Rules have been amended vide Notification No. 9/2020-Customs(N.T.) dated 2nd February, 2020, wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted incorporating the following provisions:

“the period of investigation shall,-

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

- d. After examining the arguments of the Applicants, the Authority has considered appropriate for selection of 6 months as POI given the justification provided by the Applicants as mentioned above as it would not be appropriate to fix a period for which there is no allegation of dumping.
- e. As regards arguments of M/s. Deepak Phenolics Ltd. facing start-up costs and technical problems, it is noted that M/s. Deepak Phenolics Ltd. has fully capitalized its startup cost and the same have not been included in the injury data. Further, the company achieved good capacity utilization even within 2018-19 and hence the cost of production of the company could not have been higher due to possible underutilization of new production facilities.
- f. As regards the argument that the Domestic Industry is approaching various forums and seeking relief, it is noted that it is the prerogative of the industrial enterprise to seek recourse under various statutory or regulatory provisions.
- g. With reference to the argument of demand-supply gap, the Authority considers that possible demand-supply gap may not be a reason for depriving a Domestic Industry from seeking redressal against dumped imports causing injury.
- h. With regard to the submission of the Domestic Industry concerning the form of duty, the Authority notes that as per the Rules, the mandate of the Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of ADD, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the suitability of the form of the anti-dumping measure is decided by taking into consideration the facts of a case.

- i. The injury analysis has been done for the injury period by comparing annualised figures, and not on a monthly basis. The injury margin, dumping margin and price undercutting has been determined for the entire 'period of investigation' and for the 'product under consideration' as a whole.

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the Domestic Industry

26. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- a. For the determination of Normal Value, the Applicants have considered ICIS bulletin for monthly prices in South East Asia for Thailand and US Gulf for USA. Relevant adjustments have been made to the CFR prices to determine ex-factory prices.
- b. The Applicants have taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight to determine the export price.
- c. The dumping margin is positive and significant for both the subject countries.
- d. The normal value and export price determined on a weighted average basis will not address the extent of dumping for the reason that there is significant difference in export price within the time-period without a corresponding difference in normal value. Further, since there is no significant difference in normal value and only the export price has changed in the time-period, the dumping margin determined on the basis of weighted average of normal value and export price would be flawed. It would be most appropriate to determine the normal value on a weighted basis and compare the same with prices of individual export transactions.

G.2. Submissions of other interested parties

27. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:

- a. Exports from Thailand to India are only bulk, but the domestic sales are in both bulk and packed. The Authority is requested to make necessary adjustments to enable fair comparison.
- b. The Applicants have failed to provide any legitimate calculation or rationale with respect to adjustments made when arriving at normal value for Thailand.
- c. The Applicants have not specified the adjustments undertaken to determine the ex-factory price for Normal Value from the ICIS Reports. The validity of the ICIS Reports relied upon is unclear. It is not evident whether the ICIS Reports calculates prices in the domestic markets of the subject countries. If ICIS Reports specify local prices domestic prices, then Applicants have wrongly adjusted Ocean Freight for calculation. If the ICIS Reports do not specify local prices, then the Authority cannot rely on such a basis.
- d. The adjustments with respect to ocean freight, marine insurance, inland freight have been sought in order calculate export prices at ex-factory level. However, the Applicants have failed to provide adequate information and rationale with respect to the adjustments made.
- e. In the original application, the export price of packed Phenol was wrongly shown as less than export price of bulk Phenol, whereas in the updated petition, separate prices have not been mentioned. The accuracy and reliability of the calculations and evidences, therefore, need to be checked by the Authority.
- f. Separate dumping margins have been calculated for bulk and packed Phenol. However, no separated normal value has been calculated. Moreover, separate export prices have only been calculated in the original application. It is unclear how such separate dumping margins have been created. The Authority may kindly determine the individual margin of dumping for based on the responses filed by the exporters.

G.3. Examination by the Authority

28. Under section 9A (1) (c) of the Act, “normal value” in relation to an article, means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
 - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

29. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. PTT Phenol Company Limited (PPCL), Thailand;
- ii. M/s. Mitsui & Co (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP), Singapore;
- iii. M/s. Mitsui & Co. Ltd. (MBK), Japan;
- iv. M/s. Kempar Energy Pte. Ltd. (Kempar), Singapore.

30. It is noted that PPCL is a producer and exporter, based in Thailand. During the POI, PPCL sold its products directly to customers in India and also to all the other three parties, who are trading companies which have sold the products to customers in India. MAP, MBK and Kempar were not involved in the domestic sales of the PUC in the Thailand market. The Authority notes that the PPCL and the domestic industry have requested for due adjustments to be made due to the differences in the bulk and packed forms of Phenol. The Authority has considered their request on a preliminary basis, and notes that a more detailed assessment of this issue is necessitated after collecting additional data and evidence from the parties involved. With regard to the Normal Value of bulk/loose Phenol for the cooperating producer/exporter, the Authority notes that as per the response of PPCL the descriptions mentioned in the domestic sales transactions in Appendix 4A do not indicate different forms of Phenol i.e. Bulk or packed. For the purpose of Preliminary Findings, the Authority has considered all domestic sales of PPCL as bulk/loose, pending further examination during the course of the investigation.

31. There is no questionnaire response from any producer in USA. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

G.4 Determination of normal value**Thailand****Normal value for PPCL, Thailand**

32. From the data filed by the Cooperating producer and exporter from Thailand i.e., PPCL, it is noted that during the POI, domestic sales have been made to unaffiliated customers. The questionnaire response has been examined and it is noted that the respondent has provided domestic sales price details of the subject goods in respective Appendices with proper costing data for mandatory tests. As regards normal value, the Authority notes that *** MT has been sold in the domestic market at

a price of US\$ ***/MT. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with volume of exports to India, therefore, domestic sales have been considered for the purpose of determining normal value. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80% by volume. Further, PPCL has claimed Inland Freight, Storage Cost, Credit Cost, Surveyor Cost and other related adjustments as post factory expenses. For the purpose of the preliminary findings, the claims made by PPCL have been accepted, subject to the verification of the information filed. The adjustments claimed by PPCL have been provisionally verified and accepted subject to detailed verification. It is also noted from a perusal of import information received from DGCI&S, and cooperating producers/exporters that all imports of subject goods are in bulk/loose form only, and hence no separate Normal Value determination has been made for packed/drum Phenol. The Normal Value of PPCL so determined on a provisional basis is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for Non-Cooperative exporters in Thailand

33. The Authority notes that no other exporter/producer from Thailand has responded to the Authority in present investigation. It is also noted from a perusal of import information received from DGCI&S that all imports of subject goods are in bulk/loose form only, and hence no separate Normal Value determination has been made for packed/drum Phenol. For all the non-cooperative exporters/producers in Thailand, the Authority provisionally determines the normal value on the basis of facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all producers and exporters in USA

34. The Authority notes that no exporter/producer from USA has filed questionnaire response in the present investigation. It may be noted that the Applicant had determined the normal value in USA on the basis of ICIS reports. None of the interested parties have provided any other information with regard to normal value in USA, nor have provided any evidence to show that this evidence is not appropriate. It is also noted from a perusal of import information received from DGCI&S that all imports of subject goods are in bulk/loose form only, and hence no separate Normal Value determination has been made for packed/drum Phenol. The normal value in US has, therefore, been determined on the basis of facts available i.e. prices reported in ICIS reports. The Normal Value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.5. Determination of export price

Export Price for PPCL, Thailand

35. PPCL has filed questionnaire response along with its unrelated trading companies, namely, Mitsui & Co., Ltd (“MBK”), Mitsui & Co (Asia Pacific) Pte Ltd. (“MAP”), Kempar Energy Pte. Ltd. (“Kempar”), Tradechem International FZE (“Tradechem”) and Riveredge International PTE Ltd (Riveredge). In their questionnaire response, PPCL has declared that the company has exported the product to India directly as well as through unrelated foreign traders namely MBK, MAP, Kempar, Tradechem and Riveredge International PTE Ltd, Singapore. The Authority notes that some of the exports were made by MAP through a related importer namely Mitsui & Co. India Private Limited, who has not filed its separate questionnaire response. The export price at which subject goods have been sold by PPCL to MAP, MBK and Kempar; and the price at which MAP, MBK and Kempar have exported to India have been examined, after taking into account the associated expenses incurred by MAP, MBK and Kempar. The Authority notes that PPCL has exported ***/MT of the PUC during POI to India, and out of ***/MT, ***/MT has been exported to India through the cooperating channel of trade.
36. It is noted that MAP, MBK and Kempar have exported the product at a price above costs, after taking into account the expenses incurred by them. There is no evidence of any compensatory arrangement, nor any other reason to justify rejection of producer’s price and adoption of trader’s

price. All the trade channels of exports to India are found to be profitable, therefore, the Authority has considered the prices of PPCL, the producer, to determine the ex-factory export price. Further, the producer has claimed Shipping Cost, Surveyor Cost, Handling Charges, Storage Cost, Commission, Credit Cost and Bank Charges as post factory expenses for making exports to India. For the purpose of preliminary findings, the claims made by PPCL has been accepted subject to the verification of the information filed.

37. The Authority notes that two traders, namely, Tradechem International FZE, and Riveredge have not submitted the exporters questionnaire response containing the requisite information for the said ***MT quantity exported to India during the POI. In accordance with provisions of Explanation (b) to sub-section (1) and sub-section (6A) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, and Rule 6(8) of the AD Rules, the export price for ***MT for which the complete chain of responses containing the requisite necessary information has not been submitted to the Authority, has been determined based on the facts available. The Net Export Price for PPCL has been determined on a provisional basis, subject to detailed verification on a weighted average basis after taking into account all exporting channels as mentioned above (cooperating as well as non-cooperating) and weighted average Net Export Price, as shown in the dumping margin table below.

Non-cooperative Exporters from Thailand

38. The export price for the non-responding producers/exporters from Thailand has been determined on the basis of facts available taking into account the export transactions of the responding exporter.

Export Price for USA

39. None of the exporters/producers from USA have filed questionnaire response. Due to this non-cooperation, the Authority has provisionally determined the export price for all the exporters from USA based on the imports reported in the DGCIS, and adjustments as per facts available under 6(8) of the Rules.

G.6 Determination of dumping margin

40. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been provisionally determined as follows:

Producer	Normal Value/ CNV	Export Price	Dumping Margin		
	(US\$/MT)	(US\$/MT)	((US\$/MT)	(%)	(Range)
PPCL, Thailand	***	***	***	***	0-10
Other exporters from Thailand	***	***	***	***	10-20
All producers/ exporters from USA	***	***	***	***	10-20

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the Domestic Industry

41. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the injury and causal link:
- Due to the imposition of ADD by China, countries have shifted their exports to India.
 - In view of the fact that prices of Phenol declined very substantially over the proposed POI despite no or insignificant decline in cost on account of raw material, month-wise analysis during the POI is requested.
 - Demand for the PUC has increased over the injury period.
 - The imports from the subject countries, in absolute terms as well as in relation to production and consumption, first declined and thereafter, increased in the POI.
 - Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry and are depressing the prices of the Domestic Industry.

- f. Production, capacity, and capacity utilization of the Domestic Industry has increased with commencement of production by M/s. Deepak Phenolics Ltd.
- g. The inventories of the Domestic Industry are piling up.
- h. The profitability declined severely over the injury period and the Domestic Industry was in losses during the POI.
- i. The PBIT and ROCE is negligible during the POI.
- j. Imports are impacting the ability of Domestic Industry to raise capital investment.
- k. Imports from subject countries pose a threat of material injury to the Domestic Industry.
- l. Exporters in the subject countries have excess and freely disposable capacities.
- m. Thailand has imposed restrictions on import of the PUC, thereby closing the market for global exporters, making India a lucrative market.
- n. Factors other than dumping are not causing injury to the Domestic Industry.
- o. Price undercutting being caused by the dumped imports has led to the decline in selling prices of the Domestic Industry.
- p. Despite existence of sufficient demand, the Applicants have to undertake exports at losses.

H.2. Submissions of other interested parties

42. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to Injury and causal link are as follows:
- a. No reliable evidence has been provided for claim of 12,009 MT of the goods imported in April-May 2019, which were lying in stock in the POI.
 - b. The method of 'adjustment' adopted by the Domestic Industry for calculation of imports is unclear, non-transparent and has led to double counting. As per the methodology, imports should have decreased for POI, but instead increased substantially. The consistent practice of the Authority is to rely on DGCI&S and DGS data in trade remedy investigations. If the argument of adjustment is accepted, the problem would arise in every investigation.
 - c. Domestic Industry had made obscure and inaccurate submissions regarding the import volume in the Safeguard investigation against imports of Phenol into India as well.
 - d. The consistent practice of the Designated Authority is to take all import transactions from a country into account for determination of price undercutting, not merely the positive transactions only. As per the submission of Domestic Industry, even if there is one single positive undercutting transaction, the determination should be positive based on the transaction. The Domestic Industry has relied on the WTO Panel Report dated 14th November, 2001 in the case of European Communities – ADD on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil. The claim of the Domestic Industry is incorrect. The European Union (EU) did not rely only on undercutting import transactions for determining price undercutting. They calculated the consequence of disregarding non-undercutting sales as well. The difference between the two calculations was marginal and did not affect the determination materially. The same might not be the case in the current investigation and will lead to highly distorted results.
 - e. The Domestic Industry has also stated that the injury margin should also be determined by taking into account only the injurious transactions, i.e. where the landed value is lower than the NIP. The Domestic Industry has submitted that EU, which also follows the principle of lesser duty rule, determines injury margin after excluding non-injurious export transactions. Since the practice has not been challenged in the WTO, the Authority should also consider only those transactions that are below NIP. The Domestic Industry has made reference to the Hon'ble Tribunal's order in the matter of Kothari Sugars & Chemicals Ltd. Vs. Designated Authority. Just because the practice has not been challenged in the WTO yet, does not automatically make the practice valid. ADD can be levied based on the injury margin if injury margin is lower than the dumping margin. If the Domestic Industry's argument is accepted, there would not be any

cases where injury margin would be negative resulting in nil duty for the exporter. Any unwarranted exclusions of transactions from injury margin will directly have an impact on the quantum of ADD. The EU had clarified that the undercutting margin determined by excluding non-injurious imports was also 'one of the methodologies' to assess the effect of price undercutting. The Domestic Industry has incorrectly relied on the decision of Hon'ble Tribunal in Kothari Sugars & Chemicals Ltd. vs. Designated Authority to substantiate its claim. The Hon'ble Tribunal in this case did not lay down any blanket legal proposition or rule that import transactions that are above NIP should be excluded for the purpose of injury margin calculation.

- f. There is no increase in imports from subject countries in absolute terms or relative to consumption or production in India. In the face of the huge increase in production by the Domestic Industry, the subject imports are insignificant in nature. The Domestic Industry has claimed that the USA, EU, Korea RP, Japan and Thailand diverted their exports from China PR to India after the imposition of a provisional ADD by China PR in May 2019. However, data indicates that imports have reduced after May 2019. The imposition of a provisional ADD by China PR has clearly not affected the imports coming into India.
- g. Price undercutting from the subject imports was negative for April, 2018-June 19(A) and POI(A) in the case of imports from the USA, which negates any claim made on price effect. Further, the import price has moved in consonance with the cost of sales of the Domestic Industry.
- h. The domestic selling price has moved commensurately with the shift in cost of sales. No claim of price suppression or depression can be made by the Domestic Industry on this count.
- i. An analysis of relevant economic parameters shows that the Domestic Industry has shown improvement in the performance in almost all relevant economic parameters including capacity, production and sales as seen from the updated Application and Annual Reports.
- j. The Domestic Industry has rapidly been increasing its market share over the injury period, despite the rise in demand.
- k. M/s. Deepak Phenolics Ltd. alone holds around 55% of the share in a market. It is obvious that the share of subject imports in the market would be insignificant in nature.
- l. The Domestic Industry has faced no injury in terms of employees, wages and productivity per day.
- m. The profitability of the Domestic Industry in the POI is not affected by the domestic sales, but by the high interest and depreciation costs incurred by it.
- n. Injury, if any, caused to M/s. Deepak Phenolics Ltd. is due to start-up difficulties resulting from delay in commencement of commercial production and unfair pricing policy.
- o. There is no mention of 'dumped imports' in the report presented by M/s. Deepak Phenolics Ltd. in its investor communication.
- p. No causal link as in the year 2018-19, the volume of subject imports was the highest at 123,727 MT, but the Domestic Industry made the highest profits in 2018-19. Moreover, import volume is substantially lower in the POI(A) than the volume in 2018-19, however, the PBIT has fallen for the domestic industry in the POI(A).
- q. The absence of co-relation between import volume and profit parameter of the Domestic Industry shows that there is no causal link between imports and injury to the Domestic Industry.
- r. There are strong prima facie reasons to believe that the data furnished by the Applicants is not validated with the actuals on the published final accounts in the terms of the Balance Sheet in order to validate the claim on NIP, injury and alleged dumping.
- s. One of the producers in India is known to have been exporting its Phenol at price below US\$ 750 in recent times and yet claims injury from imports into India on a comparable or similar price added with the protection of Basic Customs Duty.

- t. There must be a transparent determination of NIP based on at least one key raw-material pricing, i.e. Benzene. The present methodology employed by the Applicants skews the NIP in favour of the domestic producers and destructs the consumer industries. International prices of Benzene and Polypropylene are volatile and are falling at all time low levels.
- u. The methodology employed by the Authority by way of a reference price converted in US\$ or fixed ADD are both inappropriate distortions of Rule 17(1)(b).
- v. The Applicant has not provided supporting evidence with regard to the free disposable capacities in exporting countries.
- w. The Annual Report of M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. indicates high interest, depreciation and employee wages cost as cause of injury. The Report has acknowledged that the company achieved record production for Phenol and that feed stock prices are higher in India compared to other exporting countries and the Indian producers are at competitive disadvantages due to higher overhead costs.
- x. The consistent practice of the Authority is to analyse the Post-POI data for threat of material injury claims. However, latest information of M/s. Deepak Phenolics Ltd. shows no threat of material injury. The results for the last quarter of 2019-20 as per the Audited Financial Report for M/s. Deepak Nitrite Ltd. show 33% rise in PBIT from 40.5 Crores to 63.60 Crores. Year on year comparison shows PBIT and Revenue have become almost double in 2019-20 as compared to 2018-19. For M/s. Deepak Phenolics Ltd., the overall sales revenue of the company increased by 23% from Q2 to Q3 and overall profit has increased significantly from Q2 to Q4 showing no threat of Material injury. Recent import data also shows a declining trend in the import volumes for 2018-19 compared to annualized figures for April, 2019 to January, 2020. It is mandatory for the Authority to consider existence of all the factors enumerated for the purposes of concluding threat of material injury/likelihood.
- y. The method of adjustment with regard to injury considering M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd.'s capacity utilization at 80%, provided by the Applicants is non-transparent and appears to be deliberately obfuscated to prevent the interested parties from commenting meaningfully.
- z. The Authority has also noted the problem faced by M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. on account of availability of raw material in an anti-dumping investigation on imports of Acetone from Japan and Thailand.
- aa. If the only remaining Domestic Industry member is M/s. Deepak Phenolics Ltd., then it should have made an allegation on material retardation rather than material injury.
- bb. No reason has been provided for adjusting the data for only 2016-17 and 2017-18 as opposed to the entire injury period. To show inflated injury, the Applicants have tried to present combined figures and taken a base year of 2016-17 even though they have readily acknowledged that the injury suffered by other Domestic Industry members is on account of extraneous factors.
- cc. While the volume of imports from Thailand has decreased as the profitability of the domestic industry has also decreased. The volume of imports from Thailand has not adversely affected the profitability of the Applicants.
- dd. Owing to the strong sales and profitability performance, the claims with regards to inventories are unsubstantiated.
- ee. A mandatory BIS certification requirement, as notified by the Government, will act as a deterrence with respect to increased imports in the foreseeable future.
- ff. The Applicants experienced their largest decline in profitability in April–June, 2019, a period in which the price undercutting for Thailand was negative. Thus, no evidence that price undercutting from Thailand can be linked to the Applicants' significant drop in profits.
- gg. The Authority should scrutinize the poor performance of M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. and find that any alleged injury suffered by M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. is a consequence of their own continued inefficiencies and not attributable to the subject imports.

- hh. There is a break in causal link between alleged undercutting and performance of the Domestic Industry. Also, the Applicants have failed to provide any reasoning beyond mere conjecture that the import restrictions from Thailand will lead to more imports being directed to India.
- ii. Continued injury of the Indian industry despite the presence of duties, indicates that any injury suffered by the Domestic Industry must be on account of extraneous factors.

H.3. Examination by the Authority

43. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

H.3.1 Cumulative assessment

44. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
45. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.
46. As regards the issue of cumulative assessment in terms of para (iii) of the Annexure-II of the Rules, it is noted that the imports from subject countries fully satisfy the criteria of para (iii) of the Annexure-II. Therefore, the contention of the other interested parties about cumulative assessment are not correct.
47. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.
48. Rule 11 of the Rules, read with Annexure II, provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

49. With regard to import volumes and prices, the Authority has relied upon the import information of DGCIS and information provided by the cooperating producers and exporters from Thailand.
50. As per the consistent practice of the Authority, all import transactions have been taken into account for determination of price undercutting and for determining injury margin.
51. The Authority notes that M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. had very low production in 2016-17 and 2017-18. The company admitted that this was due to significant working capital problems faced by the company. The Authority considers that the reasons for low production by the company during this period were not attributable to dumping in the country and were due to “other factors”. The Authority has, therefore, evaluated the performance of Hindustan Organics Chemicals Ltd. in respect of profits, cash profits and return on investments, considering the capacity utilization achieved in the POI.
52. With respect to the issue raised that the data furnished by the Applicants is not validated with the actuals on the published final accounts in the terms of the Balance Sheet, and the same should not validate the claim on NIP, injury and alleged dumping, it is noted that the Authority has examined the information furnished by the domestic industry on the provisional basis subject to detailed verification, and the information submitted by the producers and exporters for normal values and export price have also been provisionally accepted subject to detailed verification.
53. With respect to the argument that the method of ‘adjustment’ adopted by the Domestic Industry for calculation of imports is unclear, non-transparent and has led to double counting, it is noted that volume of import of subject goods and its prices have been determined from DGCIS data, and information furnished by the producer and exporters from subject countries.
54. As regards the submission that alleged injury to the Domestic Industry is due to other reasons and there is no injury as per statements in annual reports of the constituents of the Domestic Industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self explanatory to establish that the dumping from subject countries has caused injury to the Domestic Industry.
55. All other submissions of all interested parties with regard to injury analysis have been addressed in the following paragraphs.

H.3.2 Volume effect of dumped imports on Domestic Industry

a) Assessment of demand

56. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand for the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Sales of domestic industry	MT	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
Trend	Indexed	100	125	364	364	572	572
Subject imports	MT	110,557	108,800	146,446	117,157	43,705	87,410
Trend	Indexed	100	98	106	106	79	79
Imports attracting ADD	MT	98,657	105,275	68,332	54,665	17,283	34,566
Trend	Indexed	100	107	55	55	35	35
Other Countries imports	MT	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
Trend	Indexed	100	102	63	63	8	8
Total Demand	MT	324,477	341,215	465,481	372,385	185,634	371,268
Trend	Indexed	100	105	115	115	114	114

57. It is seen that the demand for the subject good has consistently increased during the injury period, with a marginal decline in the POI. The overall demand of subject goods have increased during the POI.

b) Import Volumes from the subject countries

58. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The factual position is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Subject Countries	MT	1,10,557	1,08,800	1,46,446	1,17,157	43,705	87,410
Trend	Indexed	100	98	106	106	79	79
Thailand	MT	57,688	87,568	96,022	76,818	30,749	61,498
Trend	Indexed	100	152	133	133	107	107
U S A	MT	52,869	21,232	50,424	40,339	12,956	25,912
Trend	Indexed	100	40	76	76	49	49
Countries attracting ADD	MT	98,657	1,05,275	68,332	54,665	17,283	34,566
Trend	Indexed	100	107	55	55	35	35
Others	MT	72,660	74,011	57,028	45,623	2,825	5,650
Trend	Indexed	100	102	63	63	8	8
Total Imports	MT	2,81,874	2,88,087	2,71,806	2,17,445	63,813	1,27,626
Trend	Indexed	100	102	77	77	45	45
Subject Imports in relation to							
Total imports	%	39	38	54	54	68	68
Trend	Indexed	100	96	137	137	175	175
Indian Production	%	254	203	72	72	34	34
Trend	Indexed	100	80	28	28	13	13
Indian Demand	MT	34	32	31	31	24	24
Trend	Indexed	100	94	92	92	69	69

59. The following is observed:

- Compared to the base year, overall volume of subject imports has declined in absolute terms and in relation to production and consumption in the country in the POI. The Domestic Industry submitted that this decline in imports was a natural consequence of significant addition of capacity to the extent of 54% of Indian demand. The Authority considers that the decline in overall imports was a natural consequence of such a significant increase in capacities in the country in a situation where there was a very significant demand-supply gap in the country. As against the established demand of 3.71 lacs MT during the present POI, the installed capacity for the product in the country before commencement of production by Deepak Phenolics Ltd. was only 76,750 MT.
- The volume of subject imports has increased in relation to total imports in India. Whereas the subject imports constituted below 40% of total imports in India in 2016-17 and 2017-18, its share increased to 54% in April, 2018-June, 2019 period and further to 68% in the present POI. Imports from subject countries, thus, constitute the majority of the imports in India.

- c. However, the volume of imports of subject goods from subject countries declined in relation to production and consumption in the country.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

60. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the NIP of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a) Price undercutting

61. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows-

Particulars Subject Countries	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed Price	Rs./MT	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
Trend	Indexed	100	111	152	152	108	108
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	20-30	(0)-(10)	(0)-(10)	0-10	0-10

Particulars Thailand	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed Price	Rs./MT	69,264	73,139	1,01,345	1,01,345	69,574	69,574
Trend	Indexed	100	106	146	146	100	100
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	20-30	(0)-(10)	(0)-(10)	0-10	0-10

Particulars USA	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87

Landed Price	Rs./MT	60,813	70,371	95,295	95,295	72,085	72,085
Trend	Indexed	100	116	157	157	119	119
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	30-40	20-30	(0)-(10)	(0)-(10)	(0)-(10)	(0)-(10)

62. It is seen that the imports from subject countries are entering at a price below the domestic selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting.

b) Price suppression and depression

63. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period. The table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	113	113	96	96
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Landed price	Rs./MT	65,223	72,599	99,262	99,262	70,318	70,318
Trend	Indexed	100	111	152	152	108	108

64. It is seen that whereas the cost of sales & selling price of the Domestic Industry and landed price of imports increased till April, 2018-June, 2019, the same declined thereafter. However, the decline in selling price and landed price of imports was far more than the decline in cost of sales resulting in price suppression. It is also noted while the landed price of the imports were below the cost of production in 2016-17 and 2017-18, the same were much above cost of production in April, 2018-June, 2019. However, the landed price of imports declined below cost of production in the POI. It is thus noted that subject imports are depressing the prices of the Domestic Industry in the market.

c) Price Underselling

65. The Authority has also examined price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP determined based on average NIP for the Domestic Industry has been compared with the landed price of imports as obtained from the DGCI&S import data.

66. It is noted that the landed price of imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject country.

Particulars	Unit	Thailand	USA	Subject Countries
Import Volume	MT	30,749	12,956	43,705
Landed Value	USD/MT	970.81	1,005.85	981.19
NIP	USD/MT	***	***	***
Price Underselling Margin	USD/MT	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***
Price Underselling	Range in %	0-10	0-10	0-10

H.3.3 Economic parameters of the Domestic Industry

67. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below

68. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

69. The capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Capacity	MT	76,750	76,750	3,45,938	2,76,750	2,76,750	2,76,750
Trend	Indexed	100	100	361	361	361	361
Production	MT	43,524	53,490	2,02,461	1,61,969	1,29,280	2,58,560
Trend	Indexed	100	123	372	372	594	594
Capacity Utilization	%	57	70	88	88	93	93
Trend	Indexed	100	123	156	156	165	165
Domestic Sales	MT	42,604	53,129	193,675	154,940	121,821	243,642
Trend	Indexed	100	125	364	364	572	572

70. The installed capacity with the Domestic Industry increased significantly over the injury period. This is due to the setting up of a new plant with an installed capacity of 2,00,000 MT for phenol and 1,20,000 MT for Acetone by Deepak Phenolics at a gross investment of Rs. 1,200 crores. The plant commenced commercial production in November, 2018. The installed capacity in the Country were 76,750 MT against demand of more than 3 lacs. The Domestic Industry submitted that this investment was justified considering the significant demand-supply gap for the product in the Country.

71. As a result of setting up of significant fresh capacity, production and sales of the Domestic Industry has increased over the injury period.

ii. Market share in Demand

72. Market share of the Domestic Industry is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Domestic Industry	%	13.13	15.57	41.61	41.61	65.62	65.62
Trend	Indexed	100	119	317	317	500	500
Subject Countries	%	34.07	31.89	31.46	31.46	23.54	23.54
Trend	Indexed	100	94	92	92	69	69
Countries attracting ADD	%	30.40	30.85	14.68	14.68	9.31	9.31
Trend	Indexed	100	101	48	48	31	31

Other countries	%	22.39	21.69	12.25	12.25	1.52	1.52
Trend	Indexed	100	97	55	55	7	7
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

73. The following is noted:

- The Domestic Industry had a meagre market share earlier. The same was due to the absence of production capacities in the country and curtailment of production by Hindustan Organics Chemicals Ltd. due to working capital shortage.
- With Hindustan Organics Chemicals Ltd.'s production resuming to reasonable levels and Deepak Phenolics Ltd. commencing production in its new plant, the sales of the Domestic Industry increased significantly. Consequently, the market share of the Domestic Industry increased over the injury period.
- Whereas market share of imports from various sources declined over the injury period, as far as subject countries are concerned, the market share declined in April-June, 2019 and increased thereafter in the POI.
- The Domestic Industry has contended that the increase in the market share should also be seen along with the fact of addition of new capacities, and the price at which the Domestic Industry is selling the product.

iii. Inventories

74. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Opening	MT	***	***	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	340	340	556	556

75. It is seen that the average inventories with the Domestic Industry have increased significantly over the period.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

76. Profitability, cash profits and return on investment of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	113	113	96	96
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	114	87	87
Profit per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	120	120	(8)	(8)
Total Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	567	567	(61)	(61)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	88	621	621	127	127
Profit before Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	360	360	159	159
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	26	26	13	13

77. It is seen that:

- The Domestic Industry was earning profits up to April, 2018-June, 2019. While profit per unit increased in April, 2018-June, 2019, the same declined thereafter to such an extent that the domestic industry suffered financial losses in POI.
- Cash profit, Profit before interest and return on capital employed followed the same trend as that of profits. Cash profits, PBIT and return on investment increased in April, 2018-June, 2019 and declined thereafter till the POI.
- The Domestic Industry contended that the deterioration in performance of the Domestic Industry was continuous throughout the investigation period. It is noted that profits, cash profits and return on investments have declined significantly during the injury period.

v. **Employment, wages and productivity**

78. Employment, wages and productivity of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	April, 2018-June, 2019		POI	
				Actual	Annualised	Actual	Annualised
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	156	156	212	212
Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	188	188	223	223
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	372	372	594	594

79. It is seen that performance of the Domestic Industry has improved in respect of employment, wages and productivity. The Domestic Industry submitted that these parameters are not relevant to show the impact of dumping on the Domestic Industry.

vi. **Growth**

80. The growth of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	April, 2018-June, 2019 (A)	POI
Production	Y/Y	23	203	60
Domestic Sales	Y/Y	25	192	68
Capacity Utilisation	Y/Y	23	27	6
Average Inventory	Y/Y	10	210	64
Market share of Domestic Industry	Y/Y	19	167	58
Profit/Loss	Y/Y	(10)	526	(111)
Cash Profit	Y/Y	(12)	606	(79)
PBIT	Y/Y	(3)	273	(56)
Return on Capital Employed	Y/Y	(20)	(68)	(51)

81. It is seen that the growth of the Domestic Industry was positive in respect of volume parameters (production and sales) and negative in respect of price parameters (cost of sales, selling price, profits, and return on investment).

vii. **Magnitude of Dumping Margin**

82. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

viii. **Ability to raise capital investment**

83. Significant investment was recently made in the PUC. The Domestic Industry is suffering financial losses in the POI. With the competition being faced by the Domestic Industry because of dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The Domestic Industry is a multi-product company and, therefore, the ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone.

ix. **Factors affecting domestic prices**

84. Import prices are directly affecting the prices of the Domestic Industry in the market. It is noted that the landed value of the subject goods from subject countries is not only below its net selling price but also below the NIP of the Domestic Industry. Further, the landed prices of subject imports have depressed the prices of the Domestic Industry leading to financial losses. The imports of subject goods from third countries are either attracting ADD or are de-minimis or are at higher prices. Dumped imports are impacting the prices of the product in the market. Thus, it is provisionally concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

H.3.4. Injury Margin

85. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

86. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

87. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Name of Producers/Exporters	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
Thailand	PTT Phenol Company Limited	***	***	***	***	0-10
Thailand	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	10-20
USA	All Producers and Exporters	***	***	***	***	0-10

H.3.5 Conclusion on Injury

88. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry clearly shows that:
- i. The volume of imports from subject countries has increased in relation to total imports.
 - ii. The imports from subject countries are undercutting the prices of the Domestic Industry and the price underselling is also positive.
 - iii. Though both the selling price and cost of sales have declined during the injury period, the decline in selling price and landed price of imports was far more than the decline in cost of sales resulting in price suppression.
 - iv. The imports from subject countries have depressed the prices of the Domestic Industry.
 - v. Though the production, sales and capacity utilization has increased over the injury period, the performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The Domestic Industry has suffered financial losses in the period of investigation.
89. In view of the foregoing, the Authority provisionally concludes that the Domestic Industry has suffered material injury.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

90. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.
91. The other interested parties have submitted that the injury suffered by the Applicant is due to other reasons and not due to the imports from the subject country. The Authority notes that the interested parties have not presented any verifiable evidence establishing that the Domestic Industry has suffered injury due to factors other than dumped imports. Even though the claims made by the opposing interested parties are mere assertions, the same have been examined based on information available on record.
- a. **Volume and value of Imports not sold at dumped prices**
92. The imports from other countries are either attracting ADD or are de-minimus or are at higher prices. While volume of imports from Saudi Arabia are more than negligible, the pattern of imports over the injury period, and POI show that there is a significant decline in imports, and during POI, imports occurred only in one month. Thus, imports from other countries do not appear to have caused injury to the domestic industry.
- b. **Contraction in demand**
93. The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently grown throughout the injury period. Thus, the Domestic Industry has not suffered any injury on this account.
- c. **Changes in Pattern of consumption**
94. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the Domestic Industry.
- d. **Conditions of competition and trade restrictive practices**
95. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the Domestic Industry.

e. Developments in technology

96. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

f. Productivity

97. The Authority notes that the productivity of the Domestic Industry has increased over the injury period. Therefore, the Domestic Industry has not suffered injury on this account.

g. Export performance of the domestic industry

98. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the Domestic Industry.

h. Performance of other products

99. The Domestic Industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the Domestic Industry.

Conclusion on Causal Link

100. The Authority provisionally concludes that the Domestic Industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to subject dumped imports :

- a. The imports are undercutting the prices of Domestic Industry and are priced below the cost of the Domestic Industry.
- b. The imports have forced the Domestic Industry to sell the product at a price below cost of production. The Domestic Industry has suffered price depression on account of dumped imports of subject goods from subject countries.
- c. There is a significant decline in the import price which has forced the Domestic Industry to reduce its prices. Consequently, the domestic industry has suffered financial losses.
- d. The decline in the selling price, and consequent profits has led to decline in the cash profits and return on investment earned by the Domestic Industry.

101. The Authority, thus, provisionally concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the Domestic Industry.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

102. The Authority recognizes that the imposition of ADD might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of ADD, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of ADD, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

103. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

- a. The subject goods have been exported to India from the subject countries at dumped prices.
- b. The Domestic Industry has suffered material injury.

c. The material injury suffered by the Domestic Industry has been caused by the dumped imports.

104. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional ADD on imports of subject goods from the subject countries.

105. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional ADD equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Taking into account the factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duties on import of subject goods originating in or exported from subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central government as the difference between the landed value of subject goods and the reference price indicated in column 7 of the table below, provided the landed value is less than the value indicated in column 7.

106. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	290711	Phenol	Thailand	Any country including Thailand	PTT Phenol Company Limited	989.36	MT	US\$
2	290711	Phenol	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than Serial Number 1	992.58	MT	US\$
3	290711	Phenol	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Thailand	Any	992.58	MT	US\$
4	290711	Phenol	USA	USA	Any	1,006.96	MT	US\$
5	290711	Phenol	Any country other than country attracting anti-dumping duty	USA	Any	1,006.96	MT	US\$

L. FURTHER PROCEDURE

107. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.

- b. Domestic industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within thirty days from the date of the publication of these preliminary findings.
- c. Any other interested party may also make known its views within thirty days from the date of publication of these findings.
- d. The Authority would conduct oral hearing in terms of rule 6(6) to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
- e. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- f. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- g. The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before announcing the final findings.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Designated Authority